इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आहूत करने के समय क्या-क्या बिजनेस है, उन बातों की चर्चा निश्चित रुप से अभिभाषण मे की जानी चाहिए, वरना यह अधूरा अभिभाषण है और अधूरे अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करना संगत नही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is your opinion. Now these is no point of order because the House was summoned according to the Constitution. There is a List of Business for the House. The Government has taken note of all the things. There is no point of order.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL (NCT of Delhi) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I move that an Address be presented to the President in the following terms :-

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 12, 2009."

सर, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अभिभाषण राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों के मैम्बर्स के सामने रखा, वह इस देश के लिए एक दिशा और निर्देश है कि किस तरह हमारी सरकार पांच साल चली, क्या रास्ता हमने चुना और कैसे हमने उसे तय किया। अगर आप उनका 2004 का अभिभाषण पढ़े, तो यह लगेगा कि जिस समय वह सरकार आई थी, उस समय उन्होंने यह चुना था कि हमें अपनी आज़ादी को बचाकर रखने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं, जिससे हम एक अच्छा रास्ता तय कर सकें और हमारा देश मजबूत हो। सर, लोकतंत्र में सरकारें आई भी हैं, बनी भी हैं और चली भी है तथा उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ है। जिस समय इस देश को सन् 1947 में आजादी मिली, हमारा रास्ता शायद बड़ा कठिन था, लेकिन मन में एक भावना थी कि अपने देश को जो आजादी मिली है, इसे बरकरार रखना है और बचाकर ले जाना है। आज जब हम सरकार में हैं और हमने फैसले लिए हैं, तो आज भी वह ज़ज्बा हमारे अंदर है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए खून बहाया, अपनी जान दी और देश को आजाद कराया, तो आज जब हम सरकार में रहते हुए कोई फैसला लेते हैं, तो यह सोचते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, किस तरह हम उस रास्ते पर चल पाएंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और हमारा देश खुशहाल हो। सिर्फ सरकार मे बैठकर यह नहीं हो सकता कि हम किस तरह पैसे का बंटवारा करें और हमारा काम पूरा हो जाए। शायद जब सरकारें आती हैं, तो एक भावना होती है, अलग-अलग मल्टी-पार्टी सिस्टम है, सबका अपना वोट मांगने का तरीका हो सकता है, लेकिन जब हम सरकार में आने के लिए वोट मांगते हैं, तब हम यह कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को लागू करेंगे जिनसे हम अपने देश को आगे ले जा सकें। हम दुनियां की इस दौड़ में कहीं पीछे न रह जाएं और उन मुद्दों को उठाते हैं, जो देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। सर, इसी तरह 2004 में जब चुनाव हुए और श्रीमती सोनियां गांधी के नेतृत्व में कुछ मिली-जुली पार्टियो के सहयोग से यूपीए का गठन हुआ, कुछ मुद्दे जो चुनाव से पहले भी उठाए गए थे, उन मुद्दो को साथ में रखकर और निगाह मे रखकर, यूपीए का गठन किया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कुछ लोग सरकार मे साथ थे और कुछ पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया। जो साथ थे, वे आज भी साथ हैं, लेकिन उस समय जो बाहर से समर्थन कर रहे थे, वे आज शायद बाहर हैं। लेकिन सरकार आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ी है

और अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सर, सिर्फ कुछ ऐसे कायदे या कानून बनाने से हम देश को आगे नही ले जा सकते जब तक हमें यह मालूम न हो कि हमें किन के लिए काम करना है, हमें यह मालूम न हो कि किस रास्ते पर चलना है, हमें यह मालूम न हो कि हमारी जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, हमें यह मालूम न हो कि हमें अगले पचास साल या सौ साल का भविष्य देखकर, देश को आगे ले जाना है, तो हम किन रास्तों पर चलेंगे, हमें किस तरह काम करना होगा, क्या नीति और कार्यक्रम बनाने पडेंगे, तब जाकर हम उस दिशा में सही तरीके से जा सकते हैं। कमजोर सोच से बना हुआ देश कभी भी बहुत मजबूती से आगे नहीं जा सकता। अगर हम लोगों में देश भक्ति पैदा करेंगे और सही रास्ता इस्तेमाल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इस एड्रेस के माध्यम से मै कह सकता हूं कि जिस समय एन.डी.ए. की सरकार आई थी, तो शायद उस समय यह भावना नही रही होगी। क्योंकि पिछले पांच साल के अंदर बार-बार जब भी उनके सम्मेलन हुए तो मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की कि जिस नाम पर वे वोट मांगकर आए थे, क्या वे वोट मांगने के बाद जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कौन-सा रास्ता अख्तियार किया और उसके बाद आज किस दिशा में और किस भाषा में वे बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका जो सम्मेलन हुआ, मैंने उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि जब हम पांच साल ताकत में रहे, जब हमने सरकार चलाई, तो हमने ये-ये मुद्दे जनता की भलाई के लिए उठाए थे, इसलिए हम इस नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। अगर हम कोई भी ऐसा धार्मिक या कोई भी ऐसा मुद्दा, जिससे हमारा समाज बंटता हो या टूटता हो, उसको उठाकर वोट मांगने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम बहुत दूर तक अपने देश की आज़ादी को बरकरार नहीं रख सकते हैं। आज मुद्दा लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है। आज अगर सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे, तभी हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, मजबूत देश बना सकते है और मजबूत देश बनाने के लिए मन में उसकी कल्पना होनी चाहिए। एक अच्छी सोच लेकर, अच्छे कदम उठाकर हम आगे ले जाएं और लोगों को, जो हमारे देश में रहते हैं, उन्हें यह राहत हो कि यह सरकार आई है, यह हमारा भला करेगी, हमें दिशा देगी और हमें आगे ले जाएगी। सिर्फ रोटी-कपड़ा और मकान, जो हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है, हमारे नागरिकों के लिए हो सकता है, तब ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ हम दुनिया में भी अपनी साख बनाते हैं। हमें यह भी ध्यान रहता है कि आज हमारे किसी काम से हमारा देश छोटा न हो जाए, हमारे किसी काम से दुनिया कि दौड़ में पीछे न चले जाएं, कहीं ऐसा न हो कि लोग आगे निकलते चले जाएं और हम बहुत पीछे, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनकी गिनती में आने लगें। हमें दोनों तरीके से काम करना होगा। हमें सोच भी रखनी होगी, सरकार में आने के बाद अच्छे काम भी करने पड़ेंगे और हमें दिशा भी देना पड़ेगी। यू.पी.ए. की सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व और डॉ. मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व में पिछले पांच साल में मजबूत और ठोस कदम उठाए गए है, जिससे हमने एक दिशा हासिल की है और हम यहां तक पहुंचे हैं, जिसका विशेष उल्लेख माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि हम मजबूत हैं? हम क्यों कहते हैं कि देश हमारे हाथ में सुरक्षित है? यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद साठ साल में ज्यादातर समय हमारी सरकारें रहीं। मैं इसलिए नहीं कहता कि उस समय जब हमारे पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी बने, तो उन्होंने उस समय के भारत में जो गरीब था. उसे रोटी देने के लिए बड़े-बड़े कारखाने लगाए और दुनिया में पंचशील के माध्यम से शांति का संदेश दिया, गरीबों के दिल को छूने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि लोगों में वह जज्बा बना रहे, जो आजादी की लड़ाई में था, ताकि हम उन लोगों को अपने साथ, अपनी भावनाओं के साथ आगे लेकर चल सकें। मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधान मंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों के दिल को छूने की कोशिश की। उन्होंने वे नीति और कार्यक्रम लागू किए थे, जिससे लोगों को रोटी ओर रोजगार

मिल सके, लोग भूखे नहीं रहें। मैं यह नहीं कहता कि उस समय की जो पॉप्युलेशन थी, वे उसमें सौ फीसदी कामयाब रहे, लेकिन जो एक दिशा 1947 के बाद आजादी से शुरू हुई, उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। जब भी हमारी सरकारें रहीं, हम उस दिशा में कदम से कदम मिलाकर, कदम बढ़ाकर आगे चलते रहे और हमने लोकतंत्र को मजबूत किया। हमने लोगों में आस्था पैदा की कि नहीं, इस देश के लोकतंत्र को सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण बदला जा सकता है। अगर आप देखें तो हमारे साथ या हमारे बाद जो देश आजाद हुए, शायद वे इतनी दूरी तक अपने लोकतंत्र को नहीं ले जा सके। आज सौ करोड़ के हिंदुस्तान में चुनाव के जरिए लोग अपनी राय से किसी भी ताकतवर आदमी को हरा सकते हैं और जिता भी सकते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा और यह भावना कांग्रेस ने अपनी सरकार के द्वारा हमेशा पूरा करने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने कई कदम उठाए। उन्होंने यह देखा कि हमारा भविष्य किसमें है, हमें किस ओर जाना चाहिए। क्या हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित रह जाएंगे? उनको देने के साथ-साथ दुनिया में हमारी साख कैसे बने? हम किन मुद्दों के साथ अपने आपको जोड़ना चाहते हैं- इसीलिए उन्होंने computerization शुरू की और और भी बहुत सारी स्कीमें शुरू कीं। उन्होंने नौजवानों को छुआ। उन्होंने 18 साल के नौजवानों को voting right दिया और यह कहा कि ये हमारे भविष्य हैं। आज वही नौजवान हिंदुस्तान में तकरीबन 50-60 प्रतिशत 25 साल और उसके नीचे के हैं, जिनके हाथों में हमारा भविष्य है और जिनके लिए आज हमें काम करना है, जिनके लिए हम स्कीम बना रहे हैं, और जो दिशा दे रहे हैं, वह उनके लिए दे रहे हैं, ताकि आगे के लिए हमारा भविष्य सुरक्षित रहे।

आज हिन्दुस्तान आर्थिक रुप से मजबूत है। आज पढ़े-लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। मजबूत बैंकिंग सैक्टर है, स्थिर सरकार और मजबूत कानून-व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में हमारी भागीदारी बढ़ी है। ये वे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से आज हमारी साख अच्छी है और हम यह कहते हैं कि हमारा देश मजबूत है, सुरक्षित है, अच्छा है और ताकतवर है। शायद इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में अलग-अलग लोगों के लिए काम किया, जो अलग-अलग सामाजिक दायरे हैं, उनके लिए काम किया, जो लोग हमारे देश को अन्न देते हैं, उनके लिए काम किया। काम वे, जो रोजगार देते हैं, जो production पैदा करते हैं। सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देकर अलग-अलग मुद्दों पर उनके लिए काम किया और उनकी भलाई के लिए काम किया।

सर, सबसे पहले मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा हूं। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं, वे वहीं मुद्दे नहीं हैं, जो पिछले 50-60 सालों से चले आ रहे हैं। 5 साल के अंदर यूपीए की सरकार ने जो नए मुद्दे उठाए हैं, जो नए आयाम कायम किए हैं, जो नए बिन्दु उठाए हैं, मैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, जो हमारा किसान है, वह किसान गरीब है, कमजोर है। वह वही किसान है, जो हमें पैदावार देता है। वह वही किसान है, जो हमारी परेशानियां होती हैं, atmosphere की जो परेशानियां होती हैं, उनसे जूझता है। इसके बावजूद वह काम करता है और हमारे लिए पैदावार देता है, हमें अन्न देता है। पहले भी कई बार उनका आह्वान किया गया, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने पिछले साल उनके 76 हजार करोड़ के कर्ज़े माफ किए। सब बहुत परेशान थे, आत्महत्याएं हो रही थीं और शायद हर व्यक्ति, जो हिन्दुस्तान में रहता है, उसके मन में उनके लिए पीड़ा थी। इस पर सरकार ने सोचते हुए एक अच्छा कदम उठाया। इसलिए हमारी जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी, उसको और बढ़ावा देने के लिए उसने और कई बिंदुओं पर काम किया। उनमें से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक है, जिसमें सरकार ने 25 हजार करोड़ रखे। उसने निवेश में 300 प्रतिशत की वृद्धि की, किसानों को कर्ज दिया और उसके

साथ-साथ minimum support price भी बढ़ाई। उसने खेतिहर मजदूरों को ज्यादा पैसे देने की तरफ कदम उठाया। उसने अपन खाद नीति पर ध्यान दिया, ताकि किसानों को बराबर खाद मिल सके। उनको परेशानी न हो, इसलिए उस नीति में सुधार करते हुए उन्होंने उसकी supply सुनिश्चित की कि उनको खाद की कमी न रहे और वह खाद उनको बराबर मिले, ताकि पैदावार में कोई कमी न रहे और वह खाद उनको बराबर मिले, ताकि पैदावार में कोई कमी न आए। इसी तरह सरकार ने किसानों के लिए सिचाई की तकरीबन 14 योजनाएं शुरु की और उनके माध्यम से यह कोशिश की कि हम जिस पैदावार के भरोसे रहते हे, जिससे किसानों को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, ये वे कुछ बिन्दु थे, जिनके ऊपर उसने किसानों के दिल को छूने की कोशिश की और उस ओर उसने काम किया।

सर, इसके साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। शायद यह दुनिया में पहला ऐसा काम है, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं किया। आज के समय में किसी भी रोजगार की गारंटी देना बहुत अहम बात है, चूंकि आज सारी दुनिया में मंदी का दौर है। United States of America में कई बैंक फेल हो गए हैं, लेकिन हमारे यहां Social Welfare State है, जहां पर हम उन लोगों के लिए काम करते हैं, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं और जिनको दो वक्त की रोटी के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। उनकी तरफ देखते हुए, यह सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जिसमें उन्होंने उस गरीब आदमी को तकरीबन 100 दिन का रोज़गार देने के लिए कहा है। इसमें लगभग 55% SC-ST लोगों को काम मिला और तकरीबन 46 लाख काम इस योजना के तहत शुरू किए गए। सरकार के द्वारा इस योजना के अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपये रखे गए।

मेरा तीसरा बिन्दु नया है, वह है, "जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन"। सर, जिस समय हमें आजादी मिली थी, उस समय और आज के समय मे बहुत फर्क है। उस समय के गांवों और शहरों एवं आज के गांवों और शहरों मे बहुत फर्क है। अगर हम यह चाहते है कि हमारी सारी जनता साथ-साथ रहे, अगर हम चाहते है कि शहरों में सभी लोग अच्छे हालात में रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम यह देखें कि उनको पूरी सुविधाएं मिलें। सिर्फ एक शहर के आगे बढ़ जाने से हिन्दुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता अथवा उसकी साख नहीं बढ़ सकती। इसीलिए सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंदर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये रखे, जिससे 63 शहरों को फायदा मिलेगा और उनमें काम शुरु हो सकेगे। हमारे यहां पर जो शहर के लोग है, उनको इसका फायदा मिलेगा। तकरीबन 4 या 5 और प्रदेशों में मेट्रो सेवा चालू होगी, जिस प्रकार से दिल्ली में है और जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरह से दिन-प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, बगैर मैट्रो के शायद हम उससे कभी नहीं निपट सकते हैं। दुनिया के तक़रीबन हर बड़े शहरों के अंदर मेट्रो है। आज दिल्ली मे जो मेट्रो बनी, कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले उसकी शुरूआत की और उसके बाद अब वह अन्य प्रदेशों में भी जाएगी और इससे लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा।

एक योजना सस्ते मकान बना कर देने की है। हमारे यहां जो गरीब आदमी है, जो झुग्गी-झोंपड़ी मे रहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वे इतना पैसा कहां से कमाएं कि अपने लिए मकान बना सकें। जिस तरह से बड़े शहरों में मकानों के दाम बढ़ रहे हैं, उन दामों में कैसे वे अपने रहने के लिए छत मुहैया करवा सकें? सर, जहां हम ऐसे लोगों को रोटी और रोजगार देना चाहते हैं, वही उन लोगों को रहने के लिए छत देना भी जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि हम उनको उनके हालात पर न छोड़े। इसके लिए, ऐसे लोगों को सस्ते मकान देने के लिए सरकार पैसा लगाएगी, सरकार उसमें उनकी इंस्टॉलमेंट का कुछ हिस्सा भी देगी और जो गरीब बस्तियां हैं, वहां उनको नये

सिरे से नया मकान या फ्लैट बनाकर देगी, ताकि जिस तरह झुग्गी-झोंपड़ी में आज लोग रहते हैं, उन हालात में वे न रहें और इसके लिए उनकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। वे भी हमारे नागरिक हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्हीं से वोट मांग कर हम यहां आते हैं, इसलिए यह जो नई शुरूआत की गई है, इस पहल का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार के एक नए बिंदु को पहली बार शुरू किया गया है।

सर, इसी तरह से आरटीआई है। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा जनता का कोई भी साधारण आदमी यह जान सकता है कि हमने कब, क्या फैसला लिया, किसने लिया अथवा क्यों लिया। यह कार्य बहुत जरूरी था। अगर हम फाइलों को बंद कर देंगे तो शायद उस आदमी के अंदर वह विश्वास कभी पैदा नही हो सकता कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फिर फाइलों को दबा कर रखा भी क्यों जाए? एकाऊंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई फैसला क्यों लिया गया, इसके माध्यम से उसकी जवाबदेही होगी और अगर हम बन्द फाइलों में से इन चीजों को निकाल कर आम आदमी के हाथ में दे देंगे, तो इसके माध्यम से हम आम लोगों को यह मालूम करने की ताकत दे रहे है कि तुम फैसला तो नहीं ले सकते, लेकिन कोई फैसला क्यों लिया गया, इसे तुम मालूम कर सकते हो। यह हमारी सरकार का बहुत अहम बिन्दु है, जिसे हमने शुरु किया है। एक तरह से यह empowerment of citizen है, जिसके माध्यम से हमने उसके हाथ में यह ताकत दी है कि वह हमसे सवाल कर सके, हमारे फैसलों के अंदर क्या चीज़ क्यों हुई है, उसे मालूम कर सकें। यह एक बहुत बड़ा हथियार हमने उनको दिया है।

सर, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हमारी सरकार की पुरानी नीति रही है, चन्द्रमा पर जो चन्द्रयान गया और वहां पर उसने हिन्दुस्तान का झंडा फहराया, उसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी के साथ ही हमारे साइंटिस्ट्स ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे अब यह कहा जा सकता है कि वे सिर्फ चंद देशों तक ही सीमित नही रही हैं, उनसे अब कहा जा सकता है कि वे सिर्फ चंद देशों तक ही सीमित नहीं रही है, अब हिंदुस्तान भी उस लाइन में उनके साथ खड़ा है। आज हमारे यहां भी लांचिंग पैड्स हैं, हमारे साइंटिस्ट्स भी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और उनके अंदर कहीं किसी तरह की कमी नही है। सरकार भी आज उनको बढ़ावा दे रही है और यह उसी बढ़ावे का नतीजा है कि हमारा चंद्रयान गया। मैं उसके लिए भी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं।

सर, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सरकार ने जो मजबूत कदम उठाए हैं, मैं उनकी भी सराहना करना चाहता हूं और उसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी है। सर, आतंकवाद सिर्फ हमारे देश का मुद्दा नहीं है, आज सारी दुनिया में यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब परेशान हैं। सर, 19/11 हुआ या हमारे यहां 26/11 हुआ, वह बड़ा ही घृणित कार्य था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। यहां जो कुछ हुआ उसकी पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर से, एक नीयत के साथ भर्त्सना की। हरेक ने यह कहा कि गलत हुआ और जिसने भी किया उसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर, हिंदुस्तान की सरकार का जो रवैया रहा, उसकी जो तेजी रही, उसी के कारण पाकिस्तान को यह मानना पड़ा कि इस षडयंत्र का कुछ हिस्सा उसकी धरती से शुरु हुआ और उसकी वहां पर प्लानिंग हुई। सर, हिंदुस्तान हमेशा कड़े-से-कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा करता रहा है, लेकिन सिर्फ शब्दों को कहने भर से हम यह काम पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि अगर इस बुराई को खत्म करना है तो हमें सब को साथ लेकर निंदा भी करनी चाहिए और ऐसे कदम भी उठाने चाहिए और वे कदम हिंदुस्तान की सरकार ने यह सोचते हुए उठाए कि अगर हम आज जाग जाएंगे और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए आज नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी का गठन किया गया और एन. एस. जी. के सेंटर्स अलग-अलग प्रदेशों में खोले जा रहे हैं।

सर, यह एक अच्छा सराहनीय कदम है। हम उन्हे पैसा दे रहे है, उन्हें मजबूत बना रहे है, लेकिन जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ शायद उस समय हम ये कदम उठाते, अच्छी सोच के साथ मजबूत इरादे दिखाते और पार्लियामेंट पर अटैक के समय यह सोचते कि हम एक बड़ी खतरनाक स्थिति में आ गए हैं क्योंकि वे पार्लियामेंट तक आ गए थे, अक्षरधाम मंदिर और कई ऐसी जगहों पर अटैक हुए, अगर उस समय हम कदम उठाते, अच्छी सोच के साथ अपने मजबूत इरादे दिखाते तो शायद 26/11 हिंदुस्तान में कभी न होता। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ जब आप बोलेंगे, मैं नही बोलूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : हम आपको बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अफ़जल को फांसी हो चुकी है, उसका implementation करा दीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं आपकी तारीफ करने तो नहीं खड़ा हुआ, मैं तो अपनी सरकार की तारीफ करने खड़ा हुआ हूं।

सर, मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये बहुत अच्छे और मजबूत कदम हैं और इन्हीं कदमों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। सर, मैंने शायद "इंडिया टुडे" में एक अर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने अलकायदा के बारे में लिखा था कि आज हमें बहुत चौकस रहने की जरूरत है क्योंकि वे हमारे बॉर्डर से सिर्फ सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो मैं आशा करता हूं और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे यह सोचकर उठाए है कि आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएं। सर आज की आतंकवाद की घटनाओं में और पहले के 5 सालों की घटनाओं में बहुत फर्क है। जम्मू-कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में जो घटनाएं पहले 5 सालों में हुईं और अब के 5 सालों में हुईं, आप उनका पूरा ब्योरा देख लें तो पाएंगे कि नयी सरकार आने के बाद जिस तरह से हमने इन चीजों को लिया, उससे उनमें कमी आयी है। मैं आशा करता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर सब लोग इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे। सर, हम सब भारतीय हैं और हमारी इस देश के प्रति भावनाएं हैं। हम इसे गिरते हुए नहीं देखना चाहते। किसी की भी बुरी नजर का हम डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय भी है और उसी लहजे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

सर, एक और चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई, वह यह कि जो नेशनल सफाई कर्मचारी, Finance Development Corporation है, जो हमारे गरीब भाई है, उनके लिए पैसा रखा गया है कि उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सके, उनको व्यवस्थित किया जा सके और उनको आर्थिक रुप से सहायता दी जा सके ताकि वह औरों से पीछे न रह जाएं। उनके लिए काम करना भी हमारी प्राथमिकता रही है।

सर, इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में जो किया, उसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है। बगैर शिक्षा के शायद हम तरक्की नहीं कर पाते। हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं और वे लोग जो एमबीए करके, पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्सेज़ कर रहे हैं, दुनिया में आज उनका नाम है और आज उनको हर जगह बड़ी तरजीह दी जाती है। हमारी आईटी इंडस्ट्री का बहुत नाम है और इसीलिए सरकार ने जो Right to Education Bill लाया, उसके द्वारा उसने 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को free education देने का अपना संकल्प दोहराया। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 18 करोड़ बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कदम उठाए गए। मिड-डे मील स्कीम के द्वारा बच्चों को आकर्षित किया गया ताकि वे पढ़ाई की ओर और अधिक अग्रसर हों। इसके साथ ही जैसा हमने बजट में और 11th Five Year Plan में उल्लेख किया है कि हमने

500 आईटीआईज अपग्रेड की हैं। 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चालू की हैं, नये कॉलेजेज़ खोले हैं। 6 नई आईआईटीज़ चालू हुई हैं और दो और चालू होने वाली हैं। 20 नये Institute for Information and Technology हैं। 7 नये आईआईएम्स हैं। Architecture of Planning के दो नये स्कूल्स हैं। हमारे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह साख बनाई है. उसमें उनको सरकार की पूरी मदद मिलती है। आज जहां हम रोटी और कपड़े की बात करते हैं, वही हम शिक्षा की भी बात करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी यही दिशा अपने अभिभाषण के अदंर कही है और सरकार की जो दिशा पिछले पांच वर्षों में रही है, वह भी उसी भावना से रही है।

(उपाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) पीठासीन हुए)

इंदिरा आवास योजना, जिसमें गरीब आदमी को 60 लाख घर बनाकर देने का हमने प्रावधान रखा, उसमें 60 लाख घर बन गये हैं और हमें उनको अलॉट कर रहे हैं। इसमें 14 लाख घर और भी बनाने का प्रावधान है। सर, यह वह गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह जिस स्तर पर है, उस स्तर से उसको बढ़ने का तभी मौका मिलेगा, जब सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। सरकार का मतलब होता है कि जिसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, उसे हम व्यवस्थित रूप में दे सकें ताकि उसके अंदर हमारे लिए काम करने का जज्बा रहे, वह और आगे बढ़ सके और उसे opportunity मिल सके।

इसी तरह, हमने 6th Pay Commission में 45 लाख सरकारी कर्मचारियों और टीचर्स के पे-स्केल्स को बढ़ाकर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।

सर, minorities के लिए एक नई मिनिस्ट्री इस सरकार के द्वारा खोली गई और उसमें National Commission for minorities has been made constitutional body. National Commission द्वारा जो हमारे Minority educational institutions हैं, उनको legal right दिये गए कि वे किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ affiliate कर सकें। उनको यह अवसर दिया गया कि उनके जो स्कूल्स है, बच्चे हैं, जो छोटी संस्थाएं है, उनको बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने का मौका मिले और वे भी दूसरे बच्चों के साथ उसी में पढाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी तरह, हमने तकरीबन 8 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान रखा है और यह गिनती आगे 40 लाख तक जाएगी।

सर, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र उसमें है। सर, पहले भी "एशियाड-82" दिल्ली में हुआ था और आज हम फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए समय बहुत कम है और सरकार जो कदम उठा रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स आरंभ होने तक वे कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके लिए जो infrastructure तैयार करने है, उसके लिए भी हम काफी काम कर रहे हैं। हमारी वे योजनाएं होंगी और गेम्स बहुत अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या जो हमारी Sport bodies है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी performance कैसी होगी, क्या वे उसके लिए तैयार है, क्या उनकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है, क्या सरकार जितना पैसा उनको चाहिए, दे रही है, क्या वे खिलाड़ी जो प्रशिक्षित किए जा रहे हैं. उनकी तरफ उन bodies का पूरी तरह से ध्यान है? यह एक बहुत बड़ा event होने वाला है और मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए है, वे बहुत अच्छे कदम है और उनके द्वारा ये games भी होंगे और हमारे खिलाड़ियों की performance भी अच्छी होगी और वे हमारा झंडा बुलंद करेंगे।

सर, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, इससे सफाई अभियान में जो दिक्कतें थीं, वे दूर होंगी। गंगा नदी हमारी life-line भी है, हम उसका आदर भी करते हैं, उसके लिए हमारे मन में बहुत भावनाएं हैं। श्री राजीव गांधी जी ने भी पहले उसके लिए एक बार शुरुआत की थी और मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे अच्छे और मजबूत होंगे। इसके साथ-साथ कई और भी मुद्दे और योजनाएं हैं, जैसे सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया, SC, ST अधिनियम बनाया, आम आदमी बीमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, उर्वरक विदेश निगम for fertilisers, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, भारत निर्माण, राजीव गांधी रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, SEZ, रेलवे का विस्तार, नए हवाई अड्डे आदि।

सर, हम जो कदम उठा रहे हैं उनसे हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, हमें हमारी दिशा का ज्ञान है। हमारे मन में जज्बा है, संकल्प है। हम अपने रास्ते को पहचानते हैं, हम नारा देकर सरकार नहीं चलाते। हमारे मन में सिर्फ सेवा और विकास की भावना होती है। हम जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों को बार बार कहते हैं, हम इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं कहते। लेकिन एक विषय है, आज सेंटर-स्टेट रिलेशन्स पर एक लम्बी बहस होनी चाहिए, आज इस बारे में बहस करने का समय है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो केन्द्र से सरकारों की ओर जाता है, शायद वह पूरा खर्च नहीं होता या सही दिशा में नहीं लगता। क्या हमारा कोई ऐसा कानून है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकें या किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई परेशानी होती है, तो हम उसे ठीक कर सकें। जैसे गुजरात में हुआ, वहां हमारी माइनॉरिटीज पर अत्याचार हुए, उस तरह की अगर कोई चीज कभी भी, किसी भी जगह होती है, तो क्या सेंटर चुपचाप उसे देखता रहेगा? हम यहां सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम यहां अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भावना से काम करते हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए खून दिया, इस देश की आजादी के लिए खून दिया, उन्होंने क्या सोचकर खून दिया था कि कैसा भारत बनाएंगे और आज जब कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस समर्थित लोगों के साथ जुड़कर सरकार आती है तो लोग यह सोचते हैं कि हम इस तरह के कायदे कानून बनाएंगे, ताकि हमारी दिशा गलत न हो, ताकि हम किसी दूसरे रास्ते पर न निकल जाएं, ताकि हमारा देश कमजोर न हो। जब सब एक साथ चलेंगे, तब देश मजबूत होगा। अगर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे तब देश मजबूत होगा। कई बार छोटे फायदे उठाने के लिए जो कोशिश की जाती है, वह फायदा लम्बी दूरी की सोच नहीं हो सकता। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें अपने देश को दुनिया में एक ताकत बनाना है, आगे ले जाना है तो यह जरूरी है कि हम मन साफ करें, सोचें कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जो दुनिया में हमारे लिए नाम पैदा करेगा। कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार हमेशा मजदूर का ध्यान रखती है, गरीब आदमी का ध्यान रखती है, उस आदमी का ध्यान रखती है, जिसके पेट में रोटी नहीं है और उसको साथ लेकर वह हिंदुस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद करती है। आज कोई विषय ऐसा नहीं है, जिसमें हम पीछे रहे हों या दुनिया में कहीं कमजोर रहे हों।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का, जो उन्होंने संदेश दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa) : Sir, I stand here to second the Motion moved by my collegue, Shri Jai Prakash Aggarwalji. I also congratulate the President of India for making an exhaustive speech, which lasted, practically, one hour and fifteen minutes. Yet, some of our

Members found some flaws in the speech. In fact, I would like to refer to the hon. Member's objection which was raised initially. If they find that something is lacking in the Address, rules are very clearly provided for that. Under Rule16 of the Rules of Procedure of this House, amendment may be moved to the Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Chairman. So, many amendments have been moved, including the one moved by Dr. Murli Manohar Joshiji...*(Interruptions)*... The hon. Member, who has raised the objection, could have moved an amendment for that purpose.

Sir, since Independence, this country has progressed tremendously. We have thousands of castes, many languages and diverse cultures. We face floods, practically every year, and, annually, we have to invest crores of rupees for preventing floods, earthquakes and tsunamis. Despite these facts, our country has marched ahead. Other economic have collapsed in such circumstances. A slight jerk in the economy makes even the developed countries collapse. We have witnessed this recently. But our country has progressed tremendously despite all these things.

Many people belonging to the weaker section of our society have risen above the poverty line. But, there are many people who are below the poverty line. They face the situation boldly and we must appreciate that. In all the circumstances, they face the situation boldly and their courage has to be appreciated. I remember a line from a Hindi film which I heard long, long back. This shows the sort of enthusiasm or determination which our children have. It says, "भीख में जो मोती मिले, तो भी हम न लेंगे, जिदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे।" This has been the objective of the younger generation since then. Therefore, we have to took into the problems of those who are still below the poverty line. I was referring to Dr. Murli Manohar Joshi's amendment. I find that the entire thinking is negative. I don't know why it is like that. And amendment has been moved to say that ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh) : Sir, these amendments have not yet been moved.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KUREIN) : Yes, they have not yet been moved.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : But, notice is there. It has been circulated to us. What I am saying is that the entire appraoch in moving these amendments to the Motion is very, very negative. Why should the Opposition have a negative approach?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, we are here to point out the defects of the speech. Therefore, they can't be positive, they have to be critical. And, they are critical.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : When will I get the opportunity to address them? I can't address them after my speech is over. Therefore, Sir, if I have received this, I have to refer to them

now. All that I want to say in one line is that the entire approach is negative. The points which I mentioned are very trivial.

This is not a Budget Speech. The President of India does not give a Budget Speech to include each and every item. Therefore, these amendments don't stand anywhere. This only shows the negative thinking on the part of one of the Members of this House.

I now come to inflation. It had risen to 12 per cent. We were humiliated for about one year by the Opposition. Although inflation rose because of certain international factors, we were humiliated. But, today; by the month of January, we succeeded in bringing it down to 5.6 per cent. During their time, the could not control inflation. When the economy wet down , you sold gold. The country's gold was sold. This is how you managed the economy when such a situation arose. Now, you are humilating the Government for high rate of inflation, but what did you do? Did you not sell the gold, the treasure of this country? Sir, we have given several important legislations to the country and one of the important legislations is the Right to Information Act. This has given right to a common man to look into the working of the Government.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, just now the hon. Member said that gold was sent abroad. That was sent by the Government which was presided over by late Shri Chandrashekharji and supported by Congress.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : Sir, I was referring to the Right to Information Act. This is historical, revolutionary legislation, which has given power to the common man to look into the affairs of the Government in very, very transparent manner. If a road is being constructed. I can take a sample from the road and see whether that is being constructed as per the standards laid down for the construction of roads. If a school is being built, I can go there and take samples. I can have any document today. I would even say that the Right to Information Act has given every citizen the status of an MLA or an MP.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

You may find this as an exaggeration. Because the Right to Information Act says, "the information which cannot be denied to an MP or MLA in the House cannot be denied to the applicant under Right to Information Act." Therefore, to that extent, the status of an average applicant under the Right to Information Act is like an MP or an MLA. This is the type of legislation that we have given to the country. The President of India has rightly referred to the concept of *अतिथि देवो भव:* Sir, billions of foreign tousists come to India. We had 3.6 billion in 2008. The figure rose to 5.37 billion in 2008. The earnings were $ 6.17 billion in 2004. They went up to $ 11.75 billion in 2008. But, Sir, whenever foreign tourists come, the job of driving them away, creating scare among foreign tourist, is done by Ram Sena, Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad. In all their policies, their objective is to drive any foreigner who comes to India. I am not giving examples. But these people or members of the Association will go to Goa, enjoy in five-star hotels, enjoy all the luxuries and indulge in all those

things which they are today objecting to on the streets. This is the dual policy of these Associations. Sir, everybody will agree that the National Rural Employment Guarantee Act is, again, a historic Act. The world is watching the implementation of this Act. We are not going, I would say, by that fast speed, but 3.4 crore of rural households were provided jobs in 2007-08. About 55 per cent of these belong to SC/ST community and 49 per cent were women. About 83 per cent of the work undertaken in 2008-09 was in the field of water conservation, irrigation and land development, as the President herself said in the Presidential Address. I again say that the world is opposing us. How dare you oppose such a legislation? Time and again, we have seen that in various debates you have been humiliating, ridiculing this Bill on the ground that there will be corruption. You do not have objection in substance. You are only saying that people will eat money. *Sarpanchs* will take money, Zila Panchayat members will take money, and so on. But, in substance, you have no ground to object to such a legislation. Again, I am referring to another historic legislation. It consists of three things. It comprises of the Land Acquisition (Amendment) Bill, Rehabilitation and Settlement Bill and a policy. So, there are two legislations and one policy. These three things are so exhaustive that in a matter of land acquisition, as and when it becomes a law, it will be a historic thing.

How could land acquisition be done with a human approach? I am taking of the human approach because before a large tract of land is acquired, a social impact assessment is called for; it is provided for here. If there is a house in a plot of land of which a person has been deprived of, at present the practice is to assess the house, assess the land, give him some money and forget it. This will not be the approach in future. The person will be given a plot of land to construct a house along with the required money. Those who are displaced from the agricultural land, land for cultivation will be given to them. This is the policy nad this is the provision in the Act also. At a place where factories are being constructed, priority will be given to such displaced persons in those jobs. Similarly, the Land Acquisition Act has been amended to bring in some changes. For instance, the definition of person interested has been changed because this makes a lot of difference where the rights of tribals, the rights of forest people are included. Then, land will be acquired only for public purpose; of course, some exception has been made as far as private acquisition is concerned. Otherwise, land will be acquired only for public purpose. Then, a mechanism has been provided. For instance, today thousands of land dispute cases are pending in District and Additional District Courts. But, here, a separate mechanism for resolving land disputes in a time-bound manner has been provided. Then, settlement proposals will be three. Suppose, a piece of land is required on an urgent basis; the person affected will be given temporary accommodation; he will not just be thrown out; he will be given that temporary accommodation till the settlement proposal comes in. Therefore, I am again saying that the Land Acquisition (Amendment) Bill, the Rehabilitation and Settlement Bill, the Rehabilitation Policy, all, are revolutionery in nature.

Sir, as has been pointed out by my colleague, Shri Jai Prakash Aggarwalji, the Prime Minister,

in his sppech last year, made certain announcements about the field of education. If we consider that package, it is going to do wonders in the field of education. Six thousand new high quality schools are proposed to be opened, one in each Block. This would serve as a model for other schools. Three hundred and seventy three colleges are going to be opened in districts, where there is no proper enrolment. Thirty universities are going to be opened. Eight new IITs, seven new IIMs, five new Institutes of Science and Research, ten National Institutes of Technology, 1000 new polytechnics, 1600 new ITIs, etc. are proposed to be opened. A gigantic programme for the education sector has been announced by the Prime Minister.

Then, Sir, I come to overseas Indians. The President of India has rightly referred to overseas Indians because their problems are also there. The Government of India has paid a lot of attention in the last two-three years to them. Twenty-five million diaspora spread across the world comes to India; they have their problems. They are being provided scholarships now. You have the creation of an India Development Foundation, the establishment of a Council for Promotion of Overseas Employment and an Overseas Workers Resource Centre, People of Indian Origin, Non-Resident India University, etc. So, the Indian diaspora are going to play an important role in our country's activities and we have to pay attention to them and the President of India, rightly so, has paid attention to them.

In the energy sector, Sir, we have now an integrated energy policy. Mines and Minerals (Regulation and Development) Act has been amended to have transparency in allotting coal blocks. The Nuclear Power Energy Programme is well known and well discussed in the House. They have been opposing it all the time as their approach has been negative. They did not want the credit to go to the Congress Party. We are not opposed to it. We shall bring it in a renewed form and renegotiate it with America.

Sir, we re-negotiated it. As far as our security is concerned, we are all concerned equally what happened in Mumbai. It is shocking and surprising. When we want to have a solution of a problem, we have to face it. There are people inside supporting openly Pakistan. As per our law, confession before police is not admissible as evidence admittedly, but it constitutes a prima facie evidence for any purpose. If we referred our dossier to Pakistan, there is nothing wrong in it. But Pakistan Administration said when this is not acceptable in your country as evidence, why should we look into it. This is what they said. The same thing, in a public meeting, hon. Chief Minister of Gujarat is quoting it...*(Interruptions)*... People clapped; people laughed...*(Interruptions)*

SHRI BALBIR PUNJ (Orissa) : It is a complete distortion of facts ...*(Interruptions)* He is referring to the Chief Minister of Gujarat ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : I have seen it on TV. People were laughing...*(Interruptions)*... You humiliated India...*(Interruptions)*... You humiliated India by quoting what Pakistan said...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Punj when your turn comes, only then you speak...*(Interruptions)*.. Nothing will go on record...*(Interruptions)* Nothing will go on record...*(Interruptions)*

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : Pakistan is giving the argument that अंदर के आदमी इनवॉल्व हैं, यहां के आदमी के बिना कुछ नहीं हो सकता। This is the argument...*(Interruptions)*... They quoted*...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please don't take the name of the person who is not here in the House...*(Interruptions)*

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : Pakistan quoted* ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please don't quote the name of the person who is not in the House...*(Interruptions)*

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : सर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप क्यों बोल रही हैं?...(व्यवधान)... Mr. Naik, you have to follow certain rules ...*(Interruptions)*...

SHRI K. B. SHANAPPA (Karnataka) : ....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please sit down ...*(Interruptions)*... Please allow him to speak ...*(Interruptions)*... I have already said, name should not be taken. Wherever name is taken that will be expunged...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : I am not quoting the name now. The Prime Minister of Pakistan was very happy. He was quoting that leader again and again by saying "हमें भारत से यह समर्थन प्राप्त हुआ है।"He is quoting the name on the National TV of Pakistan ...*(Interruptions)*...

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : सर, यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है या गुजरात सरकार पर चर्चा हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Naik there are another four Members from your party to speak.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : Ultimately, they are frustrated. The economic plan has never been in their election agenda. The standard practice of these people is that six months before the election they will forget about any development, they will not talk about any development, they will raise some issue and, therefore, poor God Ram has now been brought into election. This is ultimately their entire thing. They don't believe in roads, in schools, in bridges or canals...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ : What is he saying about ...*(Interruptions)*...

श्री शांताराम लक्ष्मण नायक : शान्ताराम मेरा नाम है, मेरे नाम में "राम" है, मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मण है और मेरी माता जी का नाम सीता है, यह मैं आपको बताता हूं।

---

*Not recorded.

श्री बलबीर पुंज :*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Naik, you will not be able to complete your speech...*(Interruptions)*. Keshava Raoji...*(Interruptions)*

डा. प्रभा ठाकुर : सर, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मि. नायक, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, विषय पर आइए। I Just reminded you of time...*(Interruptions)*

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : I am finishing within five minutes. You have got every right to project...*(Interruptions)*...

श्री बलबीर पूंज : वे क्या बोल रहे हैं, समझ में नही आ रहा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : ठीक है, बाद में समझ लेना। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार) : उनको हनुमान की गदा की जरुरत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : They tried several methods. The person, who played Ram in TV Serial, contested; the one who was playing Sita also contested. They applied in these *hathkandes*.

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिम बंगाल) : सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपको तो खुश होना चाहिए। फिर आप रॉयल्टी लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : In democracy, there is a procedure. M.P.s get elected and they elect the Prime Minister. But, their Prime Minister has been announced. They are not concerned about any parliamentary democracy. The Prime Minister is selected only after M.P.s of single-largest party assemble and the elect. But, their Prime Minister has been elected and announced; everything has been done. This is the type of Party they are having.

SHRI BALBIR PUNJ : We are not dependent on a family which will give us the Prime Minister.

श्री उपसभापति : मि. नायक, अब आप विषय पर आएं।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK : I am just pointing out their procedure to elect the Prime Minister. Then, Sir, lastly, I would like to say that there is the Constitution of India and the principle of secularism is enshrined in our Constitution. Some of these people, when they stand for election, they go before Returning Officer, take oath under the Constitution of India and all these things are done. When they become M.P.s and M.L.A.s, they again take oath. When they become Ministers, they again take oath. And, after that, they say, "We do not believe in secularism; this is Congress

*Expunged as ordered by the Chair.

secularism." This is what their approach is. Please, if you are coming to the *maidan* now, at least, sewer by the Constitution and face the people. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, we shall take up Amendments. Amendments Nos. 1 to 18.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, I move:

1. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regreat that the Address does not mention about fixing the rate of interest on loans at four per cent to check the suicide being committeed by the farmers under the burden of debt.'

2. That at the *end* of the Moton, the following be *added* namely :-

'but regret that the Address does not mention about any time frame to make the country self-dependent in the field of oilseeds and pulses.'

3. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the government guidelines for agricultural research and investigation works improving the quality of products alongwith increasing the production.'

4. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that Address does not mention about any efficient acton plan to bring down the prices of goods used for decreasing the cost of agricultural production in the country'.

5. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that Address does not mention about the announcement regarding the payment of subsidy given on chemical fertilizers directly to the farmers in the country'.

6. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regreat that the Address does not mention about the implementation of a time bound programme to convert the entire agricultural lands of the country into irrigated lands.'

7. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about incurring 6.5 per cent expenditure of Gross Domestic Product on medical system in the country as per the recommendation of the World Health Organisation'.

8. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about granting to the voters during the elections the right of rejecting the candidates whom they dislike.'

9. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about taking fully effective steps to make the administration corruption free at all its levels from village to the centre'.

10. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about implementing an effective plan for including a culture of moral and physical development in the country.'

11. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about taking effective step for making the consumer sale price fixation policy of petroleum products in the country transparent and beneficial for the steps consumers.'

12. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regreat that the Address does not mention about any plan to develop and expand the traditional cottage industries, based on labour intensive techniques instead of capital intensive techniques for creating maximum employments in the country.'

13. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that the Address does not mention about any announcement to control the consumer sale price of 354 important drugs in the country by decreasing their prices ad bringing them within the reach of common man.'

14. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regreat that the Address does not mention about necessary effective directions to get the debt disbursal policy implemented strictly by the government and private banks in the agricultural sector in the country as per the guidelines of the Reserve Bank of India.'

15. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the announcement to make the weavers living under the debt burden free of all debts in all country.'

16. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention declare the constitution of a special fund to provide relief to those numerous labourers who have gone abroad for work and have become unemployed recently.'

17. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention the changes required to bring more improvement in the procedure of appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioner.'

18. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that the Address does not mention the effective steps to be taken up immediately to tackle the situation arising due to fall of income of majority of farmers as the contribution of agriculture sector in the Gross Domestic Product of the country has become 18 per cent only.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, am*end*ment no. 19 by Shri Shivanand Tiwari-Absent.

Amendment nos. 20 to 31 by Shri Murli Manohar Joshi.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, I move :

20. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the repatriation of millions of illegal foreigners particularly *Bangaladeshis* from India who might pose threat to the security of the country.'

21. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about effective steps to be taken for increasing the flow of perennial rivers after getting them cleaned and also maintain them to remain clean by containing the sources of pollution'.

22. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that the Address does not mention about the time limit for linking of the low water flowing rivers with the high water flowing rivers of the Country.'

23. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about giving priority to the self-dependant schemes of development in the country instead of those which depend upon resources obtained from foreign countries.'

24. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that the Address does not mention about bringing essential changes in the existing policy of economic development to minimize the gap between the poor and the rich in the country.

25. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the implementation of a targeted plan for utilizing power generation capacity of hydro sector based on cheap and self sustaining means of the country.

26. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the declaration of providing economic package to promote the establishment of industries based on agro-products of the country.'

27. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret' that the Address does not mention about any plan to make available cheap and affordable medicinal system in the country at least 80 per cent people of the country by bringing comprehensive improvement in the system.'

28. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

'but regret that the Address does not mention about the steps to bring comprehensive improvement in the existing industrial policy to contain environmental pollution of the country.'

29. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about any plan for converting barren land of the country into agricultural land by promoting the cultivation of traditional medicinal plants in them.'

30. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the strategic decision to check the commercialization of medical system and education in the country.'

31. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

'but regret that the Address does not mention about the declaration to ban the recovery of Rs. 2 in the form of cess from the consumers on the sale of diesel and petrol for the construction of roads, particularly for the construction of national highways of the country.'

श्री उपसभापति : श्री प्रभात झा। संशोधन नंबर 32 से 80 तक।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

32. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में बढ़ते आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

33. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे पाकिस्तान के साथ व्यापारिक, परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध समाप्त करने तथा भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

34. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी शिविरों पर हमला कर उनको नष्ट किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

35. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

36. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में हाल ही में गठित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में व्याप्त प्रावधानों को और अधिक कड़ा किए जाने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

37. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे कृषि उत्पाद बढ़ाने और अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

38. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की किसी समयबद्ध ठोस योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

39. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में चिकित्सा क्षेत्र के लगातार हो रहे व्यवसायीकरण को रोकने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

40. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रत करने के लिए किसी ठोस कार्य-योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

41. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में असम और अन्य प्रदेशों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को रोकने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

42. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकाले जाने की किसी समयबद्ध योजना का उल्लेख नहीं है।"

43. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में सीमावर्ती चौकियों को आधुनिक बनाने की किसी समयबद्ध योजना को कोई उल्लेख नहीं है।"

44. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में सेना में एक पद एक पेंशन योजना को लागू किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

45. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा आत्महत्या की निरंतर बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

46. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने वाली योजना को गति देकर निर्धारित समय में पूरा करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

47. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

48. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरी, विशेषकर बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।"

49. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे देश के उन किसानों को, जो ऋण के बोझ तले दबकर प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, बचाने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

50. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

51. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किए जाने का कोई उल्लेख नही है।"

52. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे बुजुर्गों, महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

53. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में अदालतों में बढ़ते हुए मुकदमों को देखते हुए नई अदालतों के खोले जाने का कोई उल्लेख नही है।"

54. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे अदालतों में न्यायाधीशों की भारी कमी को देखते हुए न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

55. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में एक निश्चित अवधि में पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

56. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त करने की योजना का कोई र् उल्लेख नही है।"

57. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में लागू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कड़ाई एवं कारगर ढंग से लागू करने, ताकि जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके, का कोई उल्लेख नहीं है।"

58. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे भारत की धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था की आधार गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई प्रभावी कानून बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

59. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में श्रीलंका मे सेना और लिट्टे के बीच हो रहे संघर्ष मे मारे जाने वाले निर्दोष तमिलों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का कोई उल्लेख नही है।"

60. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सैज) की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को रोकने तथा किसानों को अधिग्रहीत भूमि के लिए उचित मुआवजा दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

61. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में सम्पूर्ण देश के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

62. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में तेजी से बढ़ रही साम्यवादी उग्रवाद. नक्सलवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने का कोई उल्लेख नही है।"

63. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के अंदर जारी माओवादी हिसा और नेपाल से अपने परम्परागत सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।"

64. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही भारी वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।"

65. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों के रास्ते देश में आ रही जाली मुद्रा को रोकने के कोई उल्लेख नहीं है।"

66. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में बांग्लादेश तथा नेपाल में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

67. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे इस अभिभाषण मे बांग्लोदश मे चल रहे आतंकवादी कैपों को नष्ट करने की किसी योजना योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

68. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में नेपाल में भारतीयों को प्रताड़ित आतंकित किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

69. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश मे अवैध रूप से मानव अंगों के हो रहे व्यापार को रोकने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

70. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों मे छोटे बच्चों के अपहरण, उनके शोषण हत्याओं को रोकने के लिए किसी प्रकार की योजना का उल्लेख नही है०।"

71. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे देश मे बड़ी मात्रा मे बनाई जा रही तथा बेची जा रही नकली दवाइयों की रोकथाम के लिए किसी योजना का उल्लेख नही है।"

72. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे कृषि क्षेत्र के सुधार हेतु गठित किसान आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नही है।"

73. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

74. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश के किसानों तथा ग्रामीणों को समुचित बिजली आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

75. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे कम ब्याज दरों पर किसानों को आवास, व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

76. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में बढ़ती बेरोज़गारी को कम अथवा समाप्त करने की किसी समयबद्ध योजना का उल्लेख नहीं है।"

77. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नौकरी से निकाले जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख नहीं है।"

78. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजे गए गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण कानून को अनुमति दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

79. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण मे कारपोरेट क्षेत्र में सत्यम जैसे घोटालों को रोकने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

80. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण में देश में बढ़ती भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।"

श्री उपसभापति : श्री भगत सिंह कोश्यारी। संशोधन नम्बर 81 से 108 तक।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

81. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक मंदी के चलते प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के नौकरी से निकाले जाने से देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का कोई उल्लेख नहीं है।"

82. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक आधार पर आरक्षण रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।"

83. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल अधिनियम किए जाने तथा इसके अंतर्गत लोकपालों की नियुक्ति कर भ्रष्टाचार रोकने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नही है।"

84. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऋण माफी योजना में खामियों को दूर करने और किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए किसी योजना का उल्लेख नही है।"

85. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश की सभी नदियों को जोड़ने की परियोजना का कोई उल्लेख नही है।"

86. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भविष्य निधि योजना सहित लघु बचत योजना पर मिलने वाली ब्याज राशि बढ़ाने का कोई उल्लेख नही है।"

87. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ मजदूरों विशेष रुप से बाल मजदूरों के उन्मूलन हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नही है।"

88. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र दिये जाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नही है।"

89. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को दिए गए ऋण की ब्याज दर घटाने की किसी योजना का उल्लेख नही है।"

90. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नही है।"

91. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को पुनर्जीवित करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।"

92. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन को बढ़ने और किसानों को अधिक सिचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

93. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान में तेजी लाने तथा उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नही है।"

94. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश मे खाद्यान्नों के मूल्यों मे बेतहाशा वृद्धि करे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।"

95. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकने की आवश्यकता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

96. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश मे बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।"

97. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे आतंकवाद से प्रभावित परिवारों, विशेषकर विधवाओं और अनाथों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत राहत देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

98. प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

99. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए किसी ठोस समयबद्ध कार्यक्रम के बारे मे कोई उल्लेख नही है।"

100. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखण्ड क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के ऋण माफ किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

101. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे में देश मे गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

102. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश में बढ़ते आतंकवाद को मूलरुप से समाप्त करने की किसी समयबद्ध योजना के बारे मे कोई उल्लेख नही है।"

103. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों जैसे टनकपुर-बागेश्वर तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना का उल्लेख नहीं है।"

104. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुद्रपुर-किच्छा सितारगंज-टनकपुर बड़ी रेल लाइन बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है।"

105. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बीपीएल व एपीएल परिवारों हेतु खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने का उल्लेख नही है।"

106. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुमायूं में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।"

107. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखण्ड में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोलने का उल्लेख नही है।"

108. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखण्ड में पर्यटन संसाधनों के विकास का उल्लेख नही है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Ramdas Agarwal. Absent. Shri Sitaram Yechury. Amendment Nos. 139 to 164, and, 171 to 173.

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, I move:

139. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to review its foreign policy."

140. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret the the Address fails to express serious concern over the global economic melt down affecting Indian industries and loss of jobs of workers and employees."

141. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to take effective part in the Non-aligned Movement."

142. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to be take up the issue of terrorist attacks in Mumbai to U.N."

143. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does has failed in mentioning the Government step in liberalizing the guidelines for Foreign Direct Investment (FDI)."

144. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address has failed to mention about the Government's move on Forward Trading."

145. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address has failed to mention the Government's abject failure to universalize Public Distribution System in the country".

146. That the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address has failed to mention about the non-availability of food to poor people in the country."

147. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the Government's failure to re-define poverty line thus wantonly deprive a majority secton of people food in the country."

148. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to tackle the huge unemployment problem in the country.

149. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention about the passage of the Women Reservation Bill."

150. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to review the Centre-State relations as per the demands of the of the State Governments."

151. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :- "but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to allot six per cent of GDP in education."

152. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address doest not mention about the failure of the Government to invest enough money in public sector and social sector to face the ongoing economic melt down."

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:-

"but regret that the Address does not mention about failure of the Government to express serious concern over the communal, parochial and chauvinistic attacks on minorities, Christians and non-Maratha people in Maharashtra and other parts of the country."

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention that 95 per cent of the 43 Crore unorganised workers will not get any benefit of the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 owing to conditionality of BPL attached to the related socal security schemes listed in the Act."

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention about the urgent need for drastically revising and/or correcting the official definition of 'poverty line' which has turned totally obsolete."

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:-

"but regret that the Address does not mention about the unprecedented price rise of essential commodities."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention the innumerable cases of suicide by the farmers during last few years in the ‘rural India’ for whom ‘a new deal’ is promised."

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention about the crisis in availability of vaccines since the Government has closed down three public sector vaccine manufacturing units viz., Pasteur Institute of India, Central Reserach Institute and BCG Vaccine Laboratories.

159. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the disastrous impact of global slow down on millions of workers who have lost their jobs, livelihood and earnings due to closure, lay off, wage-cuts, retrenchment, etc., across the sectors and also the alarming trend of sharp decline in index of industrial production."

160. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention about the lower cost of Aviation Fuel than the cost of diesel and petrol, due to flawed excise duty structure."

161. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address fails to mention about the fact that the Hyde Act is an integral part of the Indo-US Nuclear Agreement, which goes against the independent foreign policy of India."

162. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the cases of job loss of lakhs of workers engaged in diamond polishing industries in Gujarat and reported suicide of some 71 workers in Sourashtra alone."

163. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the biggest corporate scam in independent India involving more than 7000 crore by Satyam Computer Servies."

164. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the Defence contract of Rs. 10,000 crore for the supply of Air Defence Missile Systems from Israel Aircraft Industries."

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the continuous bashing of people from North India in Maharashtra by MNS."

172. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the attacks on young women in Pub in Mangalore by Sri Ram Sena."

173. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government in adeqately identifying the BPL section of the population."

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Moinul Hassan. Absent. Shri Saman Pathak. Absent. Shrimati Brinda Karat. Amendment Nos. 174 to 195.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal) : Sir, I move:

174. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret that the Address has failed to mention that the Indo-US Nuclear Deal with other aspects has seriously eroded the strategic authonomy of India's Nuclear policy."

175. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the unfulfilled assurance of Government regarding the passage of the Women's Reservation Bill."

176. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention about the continuing price rise of essential commodities."

177. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that lakhs of workers have already lost their jobs as a consequence of the global crisis and have not got any relief."

178. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the failure of the Government to counter the communal forces and to bring a suitable and appropriate legislation against communal violence."

179. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that during the last four years on an average every thirty one minutes a farmer committed suicide."

180. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that in spite of increased production, wheat was imported at prices higher than what was paid to Indian farmers."

181. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention about food insecurity, increasing hunger and malnutrition which can be addressed by increasing the reach of BPL benefits to the 77 per cent of the population who spend less than twenty ruppes a day."

182. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that Accredited Social Health Activists (ASHAs) are not being given any emoluments and that this must be remedied by giving them at least the equivalent of what Anganwadi workers received."

183. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention about the need to universalise the ICDS as directed by the Supreme Court which will have to be done."

184. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that Government has accepted the argument that institutions of excellence must be exempted for scheduled castes reservations and has pushed through a legislation to this effect."

185. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that in several cases schedule 5 of the Constitution has been violated, tribal rights superseded and MNCs and big mining companies have been facilitted in taking over tribal and forest land."

186. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention about the biggest telecom scam that has cost the Government exchequer of Rs. 1 lakh crore in granting 3G spectrum."

187. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that no steps will be taken to further liberalise the financial sector or to allow further FDI into banking and insurance sectors and pension funds of employees will be protected against any move to risk pensions by investment in the valatile stock exchange."

188. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention that the strategic relationship with the United States of America has eroded our independent foreign policy."

189. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention the necessity to break all military and security ties with Israel, as it is responsible for the Gaza genocide."

190. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the increasing acts of violence including sexual violence against women and children."

191. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address fails to mention about the need for a national mission mode to address the disturbing increase in female foeticide and declining sex ratios in the 0-5 year cateogry."

192. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the cases of job loss of lakhs of workers engaged in diamond polishing industries and reported suicide of some 71 workers in Saurashtra alone."

193. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the biggest corporate scam in independent India involving more than 7000 crore by Satyam Computer Service, reportedly enabled through political patronage."

194. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the Defence contract of Rs. 10,000 crore for the supply of Air Defence Missile System from Israel Aircraft Industries."

195. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the urgent need for Universalisation of Public Distribution System."

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Prasanta Chatterjee. Shri Tapan Kumar Sen. Not present. Okay, Shri Prasanta Chatterjee. Amendment Nos. 196 to 209.

SHRI PRASANTHA CHATTERJEE (West Bengal) : Sir, I move:

196. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention that 95 per cent of the 43 crore unorganized workers will not get any benefit of the unroganized Workers Social Security Act, 2008 owing to conditionality of BPL attached to the related social security schemes listed in the Act."

197. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention that though the Constitution (One Hundred and Eighth Amendment) Bill, 2008 for reservation of the women was introduced in 2008, the bill is yet to be passed."

198. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the urgent need for drastically revising and/or correcting the official definition of ঘpoverty lineঙ which has turned totally obsolete."

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the innumerable cases of suicide by the farmers during last few years in the ঘrural Indiaঙ for whom ঘa new dealঙ is promised."

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the unprecedented price rise of essential commodities."

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the crisis of unavailability of vaccines since the government has closed down three public sector vaccine manufacturing untis viz., Pasteur Institute of India, Central Research Institute and BCG Vaccine Laboratories."

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the irregularities leading to huge financial loss to the Government exchequer in granting 3G spectrum.

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the disastrous impact of global slow down on millions of workers who have lost their jobs, livelihood and earnings due to closure, lay off, wage-cuts retrenchment, etc. across the sectors and also the alarming trend of sharp decline in index of industrial production."

204. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention that the cost of aviation fuel is lower than the cost of diesel and petrol, due to flawed excise duty structure."

205. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the Hyde Act as an integral part of the Indo-US Nuclear Agreement, goes against the independent foreign policy of India."

206. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the cases of job loss of lakhs of workers engaged in diamond polishing industries in Gujarat and reported suicide by some 71 workers in Saurashtra alone."

207. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the biggest corporate scam in independent India involving more than 7000 crore by the Satyam Computer Services."

208. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the defence contract of Rs. 10,000 crore for the supply of Air Defence Missile System from Israel Aircraft Industries."

209. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely :-

"but regret to note that the Address does not mention about the urgent need for universalisation of Public Distribution System."

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shir Dara Singh, Absent. Shri Sharad Anantrao Joshi, Absent. Shri Pyarelal Khandelwal, Absent. Shri Shreegopal Vyas.

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, मै निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

259. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि बंगलादेशीय व अन्य घुसपैठियों को वापस करने का उल्लेख नहीं है।"

260. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि संविधान मे निहित गौ वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है।"

261. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि संविधान मे उल्लिखित समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में किसी पहल का उल्लेख नही है।"

262. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि पृथकतावाद को बढ़ावा देते हुए अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का कोई उल्लेख नही है।"

263. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि बारहमासी नदी गंगा को साफ करने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं है।"

264. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि जम्मू-कश्मीर मे घाटी के गुटों द्वारा अमरनाथ यात्रा के दौरान पृथकवादी नारे लगाए जाने और बैनर दिखाए जाने के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने का उल्लेख नहीं है।"

265. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि असम में पाकिस्तानी झंडा फहराने वालों पर कार्रवाई न किए जाने का उल्लेख नहीं है।"

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Motion and the Amendments moved are now oepn for discussion. Now, hon. Leader of the Opposition.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH) : नायब सदर साहब I heard with some attention both the proposer and the seconder of the Motion of Thanks on the President's Address. Sir, both the hon. Members are men of experience. Sir, the proposer of the Motion of Thanks is indeed a man of discrimination because he can tell the difference between right and wrong, provided he is given two guesses.

Sir, I submit -- it is an appeal I make to the Treasury Benches, in all sincerity -- that if they promise to stop speaking untruth about the NDA and the BJP, I promise, Sir, I shall not speak the truth about the Congress or the UPA. I am inclined to say this at the very beginning because we need to get some balance in this discussion which, after all, in the calendar of events of the Parliament's one yaer's life, is possibly the most important.

मैने शुरू मे कुछ लफ्ज़ अंग्रेजी मे कहे। मेरा इरादा इसके बारे मे जो कुछ मुझे कहना है, हिन्दी, हिन्दुस्तानी मे ही कहने का रहा है परन्तु आगे भी कुछ अल्फाज़ यहां आगे अंग्रेजी के आ सकते हैं।

सर, आज इस पर बोलते हुए मुझे अनुभव होता है कि यह मेरे लिए शायद 30 से ज्यादा ऐसे मौके आ गए जब मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हर बार तो नही बोला, परन्तु सब पर करीब-करीब बोलने का मौका जरूर मिला। जो सकेंडर साहिब थे, उन्होंने सही बात फरमाई कि यह बहुत लम्बा भाषण राष्ट्रपति जी का था। शायद इतना लम्बा भाषण मैंने भी कभी पहले सुना नही था। इसमें एक और बड़े पते की बात यह रही कि भाषण के दौरान इतने सारे मंत्री ऊंघते हुए मैंने कभी नही देखे। यह वाकई में अपने आप में इस भाषण का दूसरा रिकार्ड है। तीसरा रिकार्ड, नायब सदर साहब, मैं अर्ज करूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने अंग्रेजी में भाषण दिया है, तो

मैं अंग्रेजी के भाषण को ही अधिकृत भाषण समझकर कुछ दो-एक टिप्पणी अगर गुस्ताखी न समझी जाए, तो करना चाहूंगा। अगर अंग्रेजी के भाषण को लिया जाए, वैसे मेरी सहयोगी व मित्र श्रीमती सुषमा जी यहां है नहीं...। नायब सदर साहब, उन्होंने अंग्रेजी के भाषण के लिए मुझे एक बड़ा अच्छा प्वाइंट गिनाया था। इसका पृष्ठ 27 लीजिए, हम इसके आखिरी में आ जाते है, इसके दो आखिरी पैराग्राफ 81 और 82 हैं। ज़रा मेहरबानी करके गौर फरमाएं, पेज 27 पर एक वाक्य है, जो मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहां से लिया गया है। क्योंकि यह राष्ट्रपति अभिभाषण है, सोचता हूं कि यहां तो काफी तरीके से तथा खूब छानबीन करके और होशियारी से ही वाक्य लिखे जाएंगे। वहां लिखा गया है, 'At the turn of our independence' मुझे यह समझ में नहीं आया है कि इस लफ्ज का, इस sentence का मतलब क्या है? 'At the turn of the coutnry' कह सकते हैं, 'At the turn of the year' कह सकते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू तो अब राम के प्यारे हुए, फिर ये 'At the turn of our independence' क्या है? जब हम इसका अनुवाद हिन्दी में देखते हैं, तो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे चलें, पैरा-82 का जो आखिरी वाक्य है, यह तो और भी विचित्र है। नायब सदर साहब, इसमें राष्ट्रपति महोदया से कहलाया गया है, Let our reach exceed our grasp. क्या मतलब? एक तो इतना लम्बा भाषण था और जब यह खत्म होने को आया, आप तो मेरे जनदीक ही कहीं विराजे हुए थे, वहां पर तभी भी आप से अर्ज किया कि बहुत सारे मंत्री आराम फरमा रहे हैं, अपनी-अपनी कुर्सी पर। अब उसके बाद यह जो आया है, हमको तो वाकई समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें बड़ी दिक्कत आती है। अगर राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई संशोधन मंजूर कर लिया जाता है, आप तो जानते हैं, आप सीनियर मैम्बर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, इसका कोई भी संशोधन मंजूर कर लेना is equal to a vote of no confidence तो अब इसका क्या करेंगे, साहब? यह तो हमारी तकरीख में परमानेंट ही चला गया, 'At the turn of our independence' and 'reaching beyond our grasp', इसीलिए शायद मेरी सहयोगी और मित्र सुषमा जी ने कहा कि भाई साहब, जो आखिरी वाक्य है, वह भी शायद पंडित जी के नाम का ही दिया गया है। मैंने कहा कि यह पंडित जी ने कहा या नहीं, उसमें वह कह रहे हैं कि कहीं नवयुवक आशंकित तो नहीं है? क्योंकि हमको नवयुवकों की पैरवी करते-करते, इस हाउस और उस हाउस में काफी अरसा हो गया है। पहले बाल ज्यादा थे, अब उतने बाल नहीं रह गए हैं और सफेद हो गए हैं। नायब सदन साहब, मुझको कई बार अचम्भा होता है कि हमारे दोस्त कितनी आसानी से ...**(व्यवधान)**...

जल-संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : नायब सदर साहब नहीं, डिप्टी चेयरमैन ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री जसवन्त सिंह : अच्छा नायब सदर न कहें। हमें माफी बख्शिए। आपने अच्छा किया, हमें बता दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे माफ करें, मैं गलत कह रहा था।...(व्यवधान)...

श्री अरूण जेटली (गुजरात) : भाषण की लैंग्वेज भी करेक्ट कर दें।...(व्यवधान)...

श्री जसवन्त सिंह : खैर, साहब। एक लफ्ज और है, जहां फॉरेन पालिसी की बात करते हैं, क्योंकि एक दो चीजें और हैं, मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग कहेंगे कि साहब ...खैर, इसको आपको haloed की स्पेलिंग क्या है? और इसमें क्या लिखा गया है, देख लीजिएगा, हम यह सोचकर चल रहे हैं चूंकि उस पर बहस है पैरा तो सबको बाई हार्ट हो गया। एक चीज और जो बहुत गंभीरता से अर्ज करूंगा। यह जो लफ्ज है, diaspora, यह तो बिल्कुल ही गलत इस्तेमाल हुआ है। यह फॉरेन पॉलिसी की उस जगह पर है। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य रहे, दोनों सदनों में रहे, मेरा उनसे बहुत पुराना सनातन था, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी। लक्ष्मीमल्ल जी सिंघवी जी ने एक शब्द ईज़ाद किया था " प्रवासी भारतीय"बहुत सुंदर शब्द हैं और बहुत उपयुक्त शब्द भी है, जिन्हें हम expatriate इत्यादि-इत्यादि कहते हैं। मै उन दिनों से लोगों को बताता आ रहा हूं कि diaspora प्रवासी भारतीयों के लिए कहना बिल्कुल अनुचित है और इसलिए मैंने डिक्शनरी से disapora का अर्थ निकालकर देखा। अब उसमें भी दिक्कत हो गई है। क्योंकि आप इसका संशोधन नहीं कर पाएंगे? आपकी इजाजत हो तो मै अर्ज कर दूं कि the meaning of diaspora in dicitionary is, it is used collectively for the dispersed Jews after the Babylonian capctivity,

and also in the apostolic age for the Jews living outside of Palestine, now, for Jews outside Israel. अच्छा होगा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण हमको दिए जाएं-डिप्टी चेयरमैन साहब, ये छोटी बातें नहीं हैं, मैं सोचता हूं कि ये अपने आप में इस सरकार की मानसिकता की परिचायक हैं। कहने को तो बहुत मन चाहता है, जी भी करता है, परतु मैं सोचता हूं कि मैंने मेरे सहयोगी, कुशल मित्र माननीय अरूण जी से कहा था कि वे समय ले लें, क्योंकि मै बहुत संक्षेप में कुछ ही विषयों पर बोलूंगा। उसमें एक-दो बातें जरूर प्रारंभिकी के तौर पर कहना चाहूंगा। मुझे इस सबको पढ़कर बहुत तकलीफ हुई, यह सब सुनकर लगा कि यह जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, यह अपने आप में सिर्फ एक सूखी-अनमनी सी रस्म अदायगी की गई है। यह उससे आगे कुछ भी नहीं है। जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को मात्र एक खोखली रस्म अदायगी के तौर पर पूरा करने लगेंगे, जैसा इसमें आभास हुआ है, मै आपसे गलत नहीं कह सकता, तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब जानते हैं कि अभी इस सत्र की इति निकट है और सत्र के साथ-साथ जो यू.पी.ए. सरकार है, उसकी इति भी निकट ही है। वैसे अगर हम देखें तो मात्र तीस-अड़तीस दिनों में संवत्सरी आ जाएगी। ऐसा लगता है कि इस एक विषादपूर्ण परिस्थिति में, मेरे जैसा व्यक्ति एक आशा की झलक या किसी चमकती किरण की तलाश में है। इसीलिए अभी पिछले दिनों मैं दिल्ली छोड़कर दस-पन्द्रह दिनों के लिए अपने गांव चला गया था। मेरे गांव में अपनी संस्कृति की छांव में, जहां अपनी ही बोली में - चेयरमैन साहब, जैसा पहले होता था, वैसा अब कम होता है, जैसे कि यह फागुन चल रहा है, फागुन और चैत में बहुत अंतर होता है। फागुन में होली का एक उन्माद होता है और विचित्र-विचित्र, भिन्न-भिन्न नामों से देश के समूचे भाग में जो समय का परिवर्तन होता है, यह हमारी संस्कृति का एक भाग है। असम मे बीहू हो जाएगा, यहां उत्तर भारत में नीम की पोलियां आएंगी। ऐसा कहा जाता है के चैत के पंद्रह दिन यदि नीम खा लेते हैं तो साल भर कुछ नहीं होता है। काश! मेरे पास ऐसा कोई नीम नहीं है, नीम की पत्ती नहीं है, जो मैं सरकार को रिकमेंड कर सकूं। इसीलिए ये गुणी प्रभाव वगैरह भी आते हैं। उपसभापति जी, दुख होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक रस्म अदायगी क्यों रह गई। इसमें ऐसी कृत्रिमता कहां से आ गई। फिर भी यहीं सब कुछ आज की बहस का जो दारोमदार है, वह इसी स्पीच के आधार पर है, चाहे उसमें हमें जितनी भी कमजोरियां, त्रुटिया लगें।

मुझे बहुत संक्षेप में जो कुछ कहना है, मै अर्ज़ कर दूं। मैं तीन-चार मसलों पर ही अपनी बात रखूंगा। अरुण जी, अगर आप ठीक समझें, मै केवल तीन-चार ही लूंगा। सबसे पहले मै बहुत संक्षेप में सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह सुरक्षा, जिसे हम विभाजित कर देते है, जब हम आपस मे बातचीत करते हैं, चर्चा में भी हम उसको विभाजित कर देते हैं - internal security and external secuirty. यह विभाज्य नहीं है। इसका बंटवारा हो ही नहीं सकता, परन्तु हम करते हैं, तो शायद वह पुराने ढर्रे में पड़े हुए अपनी नीतियों को ढाले जा रहे हैं, इसीलिए करते हैं। दूसरा, प्रणब बाबू बहुत अनुभवी है, इस विभाग को भी पूरा देख चुके हैं, इसलिए उनसे अर्ज़ करता हूं कि यह जो शब्द डिफेंस का अनुवाद में 'सुरक्ष' आया है, इसके बारे में गौर करना चाहिए। सुरक्षा का अर्थ - सु, जो बीच शब्द है, वह है सु, उसका अर्थ है मेरा। आज की परिस्थिति में सुरक्षा शायद समुचित भावना को, भारत की रक्षा को ही लें, मेरे विचार में क्योंकि यह एक बृहद् प्रश्न है, इस पर सभी को मिल कर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बहुत चन्द बातें, नवम्बर में मुम्बई में जो हादसा हुआ, उसके बारे में कहना चाहूंगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि we then suffered what we are always suffering from, and which most elected and democratic Government also suffer from is a lacuna of actionable intelligence available in time. Friends, and hon. Members, this is not a criticism that I make against the Government; this is also not an observation or criticism that I make against the functioning of the system. It is a reality which all democratic Governments, not only democratic Government but even totalitarian Governments face. After the 9/11 incident in the United States of America, they began an inquiry. And, a wonderful and very exhaustive report

came out as to why did that happen. There is, of course, clearly an intelligence failure here, too, on 26/11 and if I cite it, it's only to underscore a continuing absence or shortcoming. There was, for example out of that absence of actionable intelligence, clearly an absence of maritime intelligence too. Therefore, that is an immediate identification of a shortcoming, along, of course, with other shortcomings, of maritime intelligence which is why, I appeal to Mr. Pranabbabu -- he's today the Government of India, in an effective and a real sense -- plese reflect, Sir, all of us need to, that for 70 hours, there was a paralysis of thought and action amongst all of us. And because you are in Government, it is your responsibility.

Now, Sir, subsequently to that, he met me personally and I am sure, Mr. Pranabbabu himself found it very humilating to do that which is not satisfying at all. And, Pakistna started playing a charade. We have the grounds for pointing out to Pakistan that this is what you have done wrong. But, Pakistan, like a charade, has converted it into a kind of question and answer session with us.

Firstly, Sir, therefore, do please order an inquiry into what happened, an intelligence inquiry. Please also reflect that after so many months of being in our captivity, this Pakistani citizen is still not in possession of all the facts. There was earlier a High Commissioner of Pakistan here, not when you were governing, much earlier, who later acquired a quite high position, and he then once told me that 'भई जसवन्त सिंह जी, हिन्दुस्तान पाकिस्तान में आप किसी थाने में किसी को भी सुपुर्द कर दीजिए और जो चाहें आप उससे कहलवा लीजिए। यहां तक कि मैं उससे मंजूर करवा दूंगा कि हां, मैंने प्रैज़िडेंट कैनेडी को गोली मारी थी।

वह यहां हिन्दुस्तान पाकिस्तान में इतने दिनों से बैठा है, अभी तक हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ सवाल-जवाब करना शुरू करें। मुझे बुरा लगता है, This is not the answer. It is a very serious challenge that was posed to India.

इसी मसले पर मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा, क्योंकि यह विषय जो अपने आप में बहुत मुख्य है, मेरे मित्र अरुण जी ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है और जरूर वह भी इस पर बोलेंगे। अगर अभी तक इसमें the conduct of the country that we are charging with misconduct, Pakistan, borders on the impertinent. Here is India that is aggrieved and with great restraint, Pranab Babu with dignity has handled it all this time, and the kind of question and answer lobbying that is taking place is firstly, inappropriate; secondly, it is inadequate; and thirdly, it is certainly impertinent on the part of Pakistan. Why is this happening? We had a strange visitor from the U.K. recently, a rather odd figure, who went as a tourist. Incidently, I am very anti-tourist, I must admit. तो यह साहबान यूपी में कहीं गायों के साथ रहने चले गए। हमको उनकी बड़ी चिंता हुई कि भई, यह मिनिस्टर है या ग्वाला है अथवा फिर क्या है? एक मैडकाउ डिसीज़ बहुत चलती विलायत में, इससे फिर हमको रायबरेली की गायों के बारे में चिंता हो

गई कि भई, यह क्या हो रहा है। सोज़ साहब, फिर वह यहां आ करके कह रहे थे कि भई, सारा मसला तो आप लोगों का है। यहां जो कुछ भी था, इस सब पर उन्होंने लेख भी लिखे हैं। This is demeaning, the great interests, the great values that India stands for. This is certainly not accetable. इसी मसले में एक चीज़ और है। I Do not want to cover that in any great detail ...**(व्यवधान)**...

PROF. SAIF-UD-DIN- SOZ : The Government was not in agreement with the views of the visitor, and the Government of India took position against certain remarks by the Foreign Minister of U.K.

श्री जसवन्त सिंह : हमें यह बात सुन करके बहुत खुशी हुई है। Even though in retrospect सर, मैं उसमें से एक दो-चीजें अर्ज करना चाहूंगा, 1993 से ले करके आज तक कितने ऐसे हादसे हुए? In 1993, there were almost 230 citizens who died, उनमें से आज तक कितने लोगों को सजा हुई है? हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है।

दूसरा, यह जो हमें लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अक़सर यह कहा करते हैं, My heart goes out to the victims. अब वह अपना हार्ट इधर-उधर इतना नही फेंके तो अचछा रहेगा।

इसके अलावा दूसरे कुछ और वाक्य भी आते हैं। एक तो इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 'We will not tolerable', तो फिर आप क्या करेंगे? पिछले 20 नवम्बर से ले करके 26 फरवरी तक ... खैर, यह मसला is not being satisfactorily resolved. I conclude this particular point by saying, by requesting, do order an inquiry into the failure of intelligence and local administration. There are two casualties in local administration. That is an admission in itself. But that admission is not accompanied by any detail of what happened One casualty is, of course, your former colleague, the former Home Minister. The other casualty is the former Chief Minister of Maharashtra. It is necessary that we have all the details; that will help us.

Sir, I will take the next point which relates to the Armed Forces. रक्षा सेनाओं का जो मसला है, उसमें मैं दो-तीन बुनियादी बातें आप से अर्ज करूंगा। Please attend to the question : why does a citizen enrol and why does he agree to die? Of course, it is a complex question, and I will not attempt an answer to this complex question here. But it remains an immensely complex question : why does a citizen agree to die? उसके पीछे, the factors that go to that decision, amongst various others are the factors of morale, of *izzat*, of *iqbal*, of standing and of the prestige of our Armed Forces, therefore, of the soldiers and sailors. Sir, there are some aspects which I have underscored; seemingly trivial, but, I think, they are profoundly important, unquestionabley important as it is, and much more important in consequence. Sir, the first question which the hon. Pranab Babu, again, in a Group of Ministers meeting was required, he chaired it, to address was the question of pay, pensions and emoluments. I will come to it in aminute.

The second is of distinction; distinction and distinctiveness of uniforms, the rights and the duties of the respective security organisations of the country. Please do not confuse one with the other. The hon. Minister, Pranab Babu, handled responsibility as the Defence Minister of the country, with

distinction and competence. And, no doubt, you realise, Sir, how, to auniformed man, whether a General or a Field Marshal or just an ordinary solider or a Warrant Officer : *izzat* is of the greatest importance. The *izzat* that the individual gets is an account of the uniform which he wears; that uniform is of this Republic of India. If you belittle the uniform, you belittle, in a very real sense, the Republic of India. फौज की जो वर्दियां है, हम देखते हैं कि ये जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां है, इसे हमारे distinguished मित्र विमल बाबू ने भी देखा होगा, कि उन कंपनियों के दरबानों को फौज की वर्दियों मे खड़ा कर देते हैं, फिर वैसे हीे मेडल्स लगाते है उन पर इस बारे में कानून बनाना चाहिए। Please do not permit the copying of military uniform by any other force, but the Military. और उसमें छोटी-छोटी बातें आ जाती हैं। फौज का चाहे रिसाला हो या पलटन, ये छोटी-छोटी बातें हैं और इन सब में कीमत देकर ही राइट एक्वायर किया गया है। सर, इसके साथ ही मैं यह example नहीं देना चाहूंगा क्योंकि उसमें वक्त लगेगा। यह जो डाउन ग्रेडिंग आपने की है of the Armed Forces, of their Officers, in the Warrant of Precedence, this is not acceptable. This is totally unacceptable. Please address it because this is a seemingly, quite seemingly, clearly an illogical and a destructive step that over the decades successive Governments of India have been continuing with and, perhaps, almost as if they have been deliberately doing it.

The next point, in additin to the point of Armed Forces, is about ex-servicemen. Ex-servicemen today number almost three million, if I am not mistaken. They are stung by the various anomalies that have been thrown up by the Sixty Pay Commission, their confusion has been compounded by a variety of interpretations that have been put out, in successive letters of the Controller of Defence Accounts'. I too, have been, for several years, the victim of the vagaries of the Controller of Defence Accounts rules, but I won't go into those details. What I am simply not understand is how the pensions of a Lt. General, a Major General and a Brigadier are going to be almost the same as that of a rank has about half the length of service, I refer to a Lt. Colonel, except, perhaps, for a difference of a hundred rupees. On what ground do you so equate? You chaired the Group of Ministers, but the discontentment remains. Precedence is very important. Pension is very important. On both counts you have dented the standing of the Armed Forces, Yet you expect them to deliver the best that they can. Sir, the question of one rank one pension has bedevilled the Armed Forces for a very long time. I am greatly troubled, I am very greatly troubled when uniformed officers and men, rather who were once in uniform are compelled to take action of the kind that they have been compelled to take, either b returning their medals or by sitting in protest. Please take our own example. I didn't hear my friends. I may be wrong. But I don't see why a Member of Parliament, should get any pension? Personally also and because it is a very unpopular thought, I know it, I am also not at all of the view as to why we should get Rs. 1 crore or Rs. 2 crores for whatever we do. But there again. I am a minority. So, I withdraw my objection. But I don't understand, when we, as Members of Parliament, have given to ourselves what tantamounts to one rank one pension, how can you deny it to the ex-servicemen? Sir, suppose a senior colleague of mine, who retired from Parliament, say, in 1957 and didn't come back to the Parliament, then the kind of pension that a Member of Parliament receives today, say, in 2009, is exactly what you will give to a Member who left the Parliament in 1957.

Between 1957 and 2009, there is a difference of almost half-a-century or so, yet you adjust the pension that you are giving him, but you refuse to adjust it for the ex-servicemen who are out of service at the age of 38. There is a full life ahead of them, but with no employment or even limited employment opportunities available. I have addressed this question in detail. Please don't throw it in my face -- you are entitled to do so - that you also held this job and why you didn't to it? Was also a Member of a Commission appointed during late Mrs. Gandi's days. Yet, perhaps because of all this. I appeal to the Government to re-address this complex question of one rank one pension, and to immediately find as equitable an answer as you can or have found for Members of Parliament. Do not let servicemen and ex-servicemen suffer on account of differentials of precedence, of pay, emoluments and pensions, and of one rank and one pension.

Sir, I will go further or to security because it is such a complex question. I wrote down what I have to say. It is the question of nuclear preparedness. We have a new Government in the United States of America. We must be very careful of their programme that awaits us. This is an area that covers both foreign policy and security.

We have nuclear know-how, we assert that we will continue to maintain our autonomy of decision-making. I appeal to the Government to reflect upon that seriously. I will take just half a minute to read out what I have to say. In order to recruit... that is and will be what is required... train and retain young talented scientists, for which our political leadership will have to articulate a vision of the laboratories that will translate into meaningful work- a mission that young scientists can embrace and to which they are then motivated enough to dedicate their lives.

Please take note that both the present US President and the Secretary of State have declared a commitment to pursue a nuclear-free world that includes a review of the NPT in 2010 and a possible revival of the Comprehensive Test Ban Treaty.

The VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KUREIN) in the Chair.

We have, therefore, as India, a rather tricky balance to maintain for the foreseeable future. We need a sufficiently capable scientific infrastructure to be the successful stewards of our capability while ensuring that it does not eviscerate the science and technology base applicable to contemporary national security challenges today and on an evolving basis. That is why, Sir, a major adjustment in governance and budgetary sources is needed to avoid any erosion of our national science and technology base and core nuclear weapons capabilities this is vital. That is why, finally 'business as usual' is not an option with respect either to the science and technology base or within the nuclear weapons laboratories. That is the very minimum that we have to do better leverage the S & T capabilities, to service an array of 21st Century national security needs.

Sir, on the external security front, I would have ideally liked to have covered the things by sharing views on a wider, sub-regional, regional, sub-continental manner, but I must compress whatever I have to submit. I must not take too much time. I must leave sufficient time for my friends and colleagues. Firstly, please take on board that we have never had as disturbed a neighbourhood as we currently do. Secondly, please also take on board -- and this is a reality; this is also the challenge

of meeting the reqirement and the complexity of the current immediate neighbourhood and external security situation -- that the problem that we face in our immediate neighbourhood is largely a consequence of the failed policies of the United States of America. That is the reality. We have to have the strongest possible relations with the USA. That is also a reality and the challenge is to find the correct and equal balance between there.

Sir, I want to cover very briefly the questions of Nepal, Pakistan and Afghanistan and this tormented triangle of our woes, the triangle constituting US-NATO presence on the subcontinent. I have a theory, Sir, which I have subscribed for long and which I had shared with my friends from the United States of America, too. There is a natural balance that this subcontinent has, from the Himalayas to the Ocean, and this natural balance gets disturbed, the minute there is any foreign elements in it. Today, we have two presences. One is the NATO-US presence and, along with it, on our eastern land, is the Peoples Republic of China. You have to recognise the reality for what it is and address the challenge on external relations and management of foreign policy accordingly. It was exactly the same when the Soviet Union moved into Afghanistan. It is again a repeat of that situation which we are facing and I find it disturbing that our approach and attitude remains that similarly subdued as it was, say, in 1979-80 when the Soviet Union invaded Afghanistan.

After Afghanistan and Pakistan, let me now briefly cover Nepal. I have a lot of points on the defence preparedness too. Therefore, before I go to Nepal, permit me to suggest just one thing, Sir. The hon. Raksha Mantri, who is a dear friend of mine, recently blamed the Government red tape for delays in modernising; and at a recent seminar he said that even though the Government had earmarked huge allocations for the military, this had not been fully reflected in our modernisation efforts. Allocation is not the problem; the issue has been of timely and judicious utilisation. That is why, whereas we are told that the Defence Expenditure, for example, of 2009-10, at Rs. 36,000 crores is a plus of so much, because of the pay increases and so on, the real increase is only 14%, that is, Rs. 13,000 crores. I recognise the difficulties; these are difficulties that we have created for ourselves.

नेपाल के बारे में राष्ट्रपति जी ने हमको फरमाया कि 'our Government extended its full support to the people of Nepal in their historic transition to multi-party democracy and we wish them well'. यह 2 Sentence भी नही है। दो लाइनें भी नही, डेढ़ लाइन है, डेढ़ sentence है। मैं नहीं सोचता कि नेपाल जैसे हमारा पड़ोसी है, वहां अभी जो हालात हैं, उसके लिए ये उपयुक्त हैं या इतना ही कहना काफी है? देश की सरकारी नीतियों ने भारत को, हमारे हितो को और इस द्वीप की एकात्मता को, हमारी सुरक्षा के खास पहलुओं को बहुत गहरी क्षति पहुंचाई है, यह मेरा सीधा चार्ज है और जैसे नेपाल में पहुंचाई है, वैसे ही श्रीलंका में उपेक्षा करके, तमिलों के हितों को पहुंचाई है। इस किस्म की निष्क्रियता ने हमारी विदेश नीति को जकड़ लिया है, जिसके परिणाम हमको कई पीढ़ियों तक भुगतने पड़ेगे, जैसे पाकिस्तान के बारे में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के गलत निर्णयों को हम आज तक भुगत रह रहे हैं, चीन के बारे में गलत नीतियों के परिणाम हम आज तक भुगत रहे है। यह अपने आप में एक तथ्य है कि आंतरिक नीतियों के बारे में कोई गलती हो जाए, तो कई पीढ़ियां लग जाएंगी उनको सुधारने में, जैसे जम्मू-स्थिति पर कोई भूल हो जाए, तो कई पीढ़ियां लग जाएंगी उनको सुधारने में, जैसे जम्मू-कश्मीर और चीन के मसलों पर है और आज मैं आपको चेतावनी देता हूं कि नेपाल और अफगानिस्तान के मसलों पर हम कहां आज के नेपाल का क्या व्यथा है। यदि नही संभले तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां मैंने एक वाक्य पढ़ा-जहां सत्य के स्थान पर और सत्य नही तो तथ्यों के स्थान पर, उन्हें स्पष्ट उजागर करने की जगह कोई मौन धारण कर ले, चुप्पी साध ले, तो वह मौन

4 P.M.

या चुप्पी, असत्य हो जाता है। Silence beyond a point, Sir, becomes an untruth. We are today the victims of the untruth of the Government of India in the way it has addressed the question of Nepal. आज नेपाल में क्या हो रहा है? मैं दो-तीन बातें कहूंगा, जो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। अभी पिछले महीने, जनवरी में, बीरगंज में एक मधेशी जनाधिकार मोर्चा बना है। बीरगंज एक मधेशी एरिया है। उस जनाधिकार मोर्च का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आया। मधेश में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहली बार आया है। मधेश यानी मध्य देश, आज यह बिहार और यूपी से लगता है। पहाड़ शुरू होता था, तराई थी, इसलिए मध्य देश कहलाता था, जो चलते-चलते अपभ्रंश होकर मधेश हो गया है। पहली बार चीन का प्रतिनिधिमंडल वहां, इस मधेशी जनाधिकार मार्चे के सम्मेलन में शरीफ होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे अखबारों में भी इसके बारे में टिप्पणी नहीं है, संसद की टिप्पणी नहीं है। वहां माओवादी टोली के एक सदस्य थे, उनको चीन ने बुलाया था। उनका शुभ नाम है, मात्रिकी यादव। वे चीन की यात्रा के बाद अभी लौटे हैं। उन्होंने मधेशिया में एक नया माओवादी दल खड़ा किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इसके बारे कुछ Object नहीं किया है। आज मधेश में 41 insurgencies चालू हैं, हमारे देश में जो बाकी ''ÖÖ†Öê¾ÖÖ¤üß' नाम से जो कुछ हो रहा है, उस पर यह माओवादी insurgencies हमारे देश के पड़ोस में है, बगल में है, हमारे कंधे के पास है। वे थारू हैं, मगर है। मगर फौज में भी बहुत भर्ती होते हैं। आप थारू जानते हैं, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। एक थारू insurgecy हो गई, एक मगर insurgency हो गई। अभी मगर insurgency में उन्होंने एक थाना लूटा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले माओवादी लूटते थे। यह हथियार तान कर प्रजातंत्र वहां नहीं लाया गया था। यह सरकार ने अपने कारनामे को छिपाने की कोशिश की है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा, संसद में अपनी बात रखना चाहूंगा कि हम संभल जाएं। Sir, I say this with great humility that the baston of the Himalayas has been breached yet again, and we now have the presence not in the hills or the mountains or the snow peaks of the Himalayas, we have them on the plains of U.P. and Bihar.

सर, मैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जो मैं उद्धत कर रहा हूं, यह अपने आप में एक अमेरिकन इंटेलीजेंस रिपोर्ट के अंश हैं। "We need to recognise just how grim the realities have become in the Afghanistan-Pakistan conflict. As recent reports, the U.S. Intelligence has produced a National Intelligence Estimate, stating that we face a steadily stronger enemy that is winning in the ways that count. Taliban, Hekmatyar, and Haqqani influence have steadily expanded in both Afghanistan, FATA and Baluchi areas of Pakistan. Sir, Swat is only 150 kilometres from Islamabad. Similar reports show that the White House has finally recognised that we have failed, and we have the troops personnel and money necessary to win the war, and there is a total rethink about the strategies. Sir, the U.S., NATO and the Afghan Government might still occasionally win a tactical clash, as may, indeed, even the Pakistan Army and the Frontier Corps, but this is not the real war. The real war is political, ideological and a struggle for the political, economic and the emotional space of that country called Afghanistan. There is a slow attrition of both at and at that place. Taliban and its allies

shall outlast the NATO and the U.S. forces. Let us, at least in India, recognise it. The United States of America might be 8,500 miles away. We are only eight-and-a-half minute away.

Just a few sentences for the reality of Pakistan. I quote in parts, a writing from Pakistan itself. The views, which I might share are of a Pakistani citizen, that ought to be writing this and making it public merits considerably greater attention on our part. He says, "I think we are not getting it. Talibansim in Afghanistan is a revolt against the American occupation. Those who can't see this deserve an extended stay in a re-education camp. From this perspective, the true godfather of the Afghan resistance is the United States of America."

This is a reputed Pakistani journalist who was himself serviceman. He says, "But Pakistani Talibanism, as represented by Baitullah Mehsud in South Waziristan and Maulana Fazlullah in Swat, is a slightly different phenomenon. It may have orginated as a side-effect of the Afghan war but it has now mutated into something with a personality of its own. With all its primitiave and even barbaric permutations--- the bombing of schools, the insistence on what amounts to female segregation, the sitting of throats --- it is a revolt against the Pakistani state. Or rather a revolt against the dysfunctional nature of this state. "We are, Sir, dealing with this reality.

There is another article that we must take note of I had an occasion to ask a friend from Pakistan who lives in Peshawar, he is a retired diplomat. I had earlier read records that Taliban was shortly going to take over Peshawar in about a fortnight's time. I asked him and he is a very senior and distinguished man himself. He said, "भाई जसवन्त, यह नामुमकिन नहीं है। हो सकता है इसीलिए मैंने अपनी बीवी-बच्चों को कहा कि इस्लामाबाद चले •जाओ।"

It has no longer struck on that region of FATA or Waziristan. It is now in Punjab. In Peshawar, Sir, let me cite to you, there is a place called Hyderabad, it is a kind of an extension of Peshawar; it would be like from here to Chandni Chowk. And, in Hayatabad, there is a place there called Mangalbagh. Do not be surprised, Peshawar was earlier inhabited by a large number of Hindi citizens. There is a *bagh* which is called Mangalbagh. Mangalbagh today is a kind of headquarters for Taliban activity.

Sir, that Taliban revolt is not subsiding. It is spreading. It was confined up till now to the FATA, but on February 7, ten days back, it saw this revolt cross the Indus River, for the first time, and a police check post in Mianwali was attacked by Taliban fighters. Mianwali and Bhakkar along the Indus are vulnerable districts open to infiltration from the Forntier. God help us in India, here if they acquire any kind of foothold there. Sir, I have just a few things to share. Sir, the People's Republic of China-China issued a defence paper, it is their Defence Paper-2008 and as an India my reaction to that Defence Paper is that they have projected or termed it the concept of 'active defence' which today is the basic doctrine of China's conventinal military strategy, its 'comprehensive national power', a very interesting phrase that People's Republic of China uses : 'comprehensive national

power' and their commitment to increase it. Sir their Defence White Paper says clearly that China's national security is no longer limited to the defence of its borders but also to screening political, diplomatic, and economic interests overseas. 'Active defence', by them as in the White Paper is also referred to as 'forward defence', whih means holding on to terriories gained and in plan terms it will mean control of land or maritime territory. In a political sense it will also reflect influencing governments, like what they are doing today in Nepal enthusiastically and in Pakistan. Sir, I won't go into other aspects of it except to highlight certain things in their nuclear doctrine, the White Paper says that the nuclear doctrine subscribes to the theory of no first use like India does. But Chai Yujiu, the Vice-Principal of the Nanjing Army Command College has stated that the policy of not to use nuclear weapons first is not unlimited, without conditions, or without premises. Sir, we have to take note of this as also of water question, which I had raised on March 5, 2008 because the Sutlej is vulnerable as is the Brahmaputra, the same as sangpo it turns in Tibet, it does a U-turn, Sir, there is a gorge there which is extremely narrow. I had requested ISRO to give me satellite photos of that and by the kind courtesy of the former Chairman of ISRO I got some of them. I urge Members of Parliament, please see those satellite photos and you will see the danger that the Brahmaputra faces today. That gorge, narrows down to almost just a 30 metres wide gorge and it descends by 1000 metres in 20 kms. That is where dam is being put up and if Brahmaputra is trapped there, them please reflect on what happens to our coutnry. I have been appealing to the Government, to this Government for the last four years and it is a matter of disappointment to me that there is not a word about it. We are a water stressed country; we cannot afford to lose the water of Brahmaputa. It happened earlier in the East on the Suffer, even now I appeal again, please advise the country, forewarm it in time. Sir, actually, I have taken more time than I should have or intended to कहने को तो बहुत कुछ है पर क्या करें। जब बहुत कुछ कहने को जी करता है तो कुछ भी कहने को जी नही करता। ऐसे हालात में हम कबीर जी को ही याद करते हैं:

"कहे कबीर नाम बिन बेरा, उठ गया हाक़िम लुट गया डेरा।"

Thank you, Sir.

SHRI SITARAM YECHURY : Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. You must excuse me, Sir, to drag a little time to reorient myself...*(Interruptions)* It must be an alarm. Anyway, I must thank the hon. Member who set an alarm, because, after hearing the hon. Leader of the Opposition's enlightened world view and the comments that he drawn our attention to very serious problems across our borders, you must grant me a little extra time to warm up to come back to my own country and talk about the issues that the President's Address has actually referred to.

Sir, I rise here, today, for the first time, in the life of this Government, when not offering ctritical support, after having withdrawn our support to this Government which was based on the National Common Minimum Programme, and I use the word 'critical' in all its senses. Our support was critical in terms of numerical strength for the survival of this Government. How it continued to survive even after we withdrew our support is a saga in moral degeneration of our Parliamentary Institution which,

unfortunately, has not found a mention in the hon. President's Address. But I also use the world 'critical' from the point of view of the critical support that we gave to this Government for the last four years. Many of the flagship programmes - whether it is the National Rural Employment Guarantee Scheme, or, whether it is a question of tribals' right to forest land, or whether it is a question of right to Infomation, or, whether it is a question of urging the Government to invest more in agriculture, or, whether it is a question to the credit waiver of farmers -- that have been listed by the hon. President in her Address and on all other crucial issues which today are the pride of this Government in the President's Address, there has been a critical role played by the Left while we were supporting this Government to ensure that these were undertaken and fulfilled.

Similarly, there was also a critical role played by the Left in stopping the Government from going ahead on many things which we thought were not in the country's interest. Those, unfortunately, again, did not find mension in the hon. President's Address. And, there are, at least, four areas which are important for us to note, because these relate, directly, to the impact of global economic recession which would have fallen on our country if we had allowed these four measures to be undertaken. The first was the full convertibility of Indian Rupee. The second was allowing foreign banks to takeover or get higher equity in Indian banks. The third was the privatisation of the Pension Funds. If that was done, along with the collapse of the world market, the life long savings of crores of Indians would have vanished. The fourth one was the increase of FDI cap in the insurance sector. If that had happened, with the collapse of the International insurance giants, you would have had a similar collapse here wiping off the lifelong savings of millions of our countrymen. On these four issues we had stopped this Government from going ahead. The hon. Preisdent refers in her Address to the fact that we have been able to withstand the global recession with much greater tenacity than many other countries. I repeat what I said earlier. I think, even if you calls us devil, the devil must be given its due, both for the positive things that have happend and the negative things that did not happen because of us. And, that is absolutely necessary to be noted which, unfortunately, does not figure in the President's Address. But, when we did withdraw our support, we withdrew it because there was a breach of the CMP on which we extended our support. And the breach occurred when the Government decided to go ahead with something which has not there in the CMP and that is the stretegic relationship or understanding with the USA on the basis of Indo-US Nuclear Deal. Now, that is not an issue on which we need to debate more, because our point of view is already known to the entire country. But, at that stage, we gave a warning and that is missing in the hon. President's Address. It is concerning the independence of our Foreign Policy. The independence of our Foreign Policy, the manner, which was also highlighted now by the hon. Leader of the Opposition, in which India ought to take its Foreign Policy positions on the basis of its own internal interests, is somehow being compromised. It is because of the strategic relationship with the USA. The CMP explicitly stated that we will have good relations with all the countries, including the USA, but will pursue an independent Foreign Policy. We will pursue a policy against the unilateralism in world politics and we will encourage multilateralism.

When that was brached, this situation had occurred and we had to withdraw support. But, unfortunately, as I said, how that was made up. We have seen that on the electronic media. We don't have to repeat it. But that is somethng, which I repeat again. That moral degeneration in our august House of the Parliament is something which all of us will have to cleanse collectively from our system. And, the absence of that in the President's Address is a matter of concern. In any case, we had warned then, we warn now, we had warned even earlier that all those who befriended the past US President have lost their jobs as the Prime Minister of various countries from England to Australia and other countries. But when our Prime Minister went and said that the whole India loved President Bush, there was a great sense of relief in the world when he was replaced and the new President took over in the United States of America. That relief was a collective relief of the world. And, that relief is also shared by the majority of Indians. Therefore, that sort of statement that we had that Indians loved George Bush was something not palatable and does not go well.

The bulk of the President's Address was concerned with the economic situation, the achievements of the Government in the economic sphere and the special emphasis that was made was on the question of inclusive growth. I think, has been a very serious omission in the President's Address -- of the grim reality in our country of widening economic disparity. I have stated this in this House earlier also, and I would like to repeat that we have two Indias in the making -- you have a 'Shining India' and, as opposed to that, you have a 'Suffering India', which is the majority of India. Our own hon. colleague, Shri Arjun Sengupta, had submitted a report to the Prime Minister where he had said that 78 per cent of the Indians live on less than Rs. 20/- a day. Now, if you calculate for a month that comes to about Rs. 600/- a month. The Planning Commission, today, I believe is revising its poverty estimates, which comes to about Rs. 400/- in rural India and Rs. 600/- in urban India. What does the Arjun Sengupta Committee Report tell us? It tells us that 78 per cent of the Indians are below the poverty line, as per Planning Commission's own new definition. But, yet, what do we announce to the world? We announce that we have a poverty line of 35.97 per cent, or, nearly 36 per cent. That is not the poverty line. That is the diestitution line. And, on the basis of the destitution line, the Government decides allocation of foodgrains for people below the poverty line. Crores of Indians are deprived of food today; crores of Indians suffer today because of these definitional problems and because of the illusion that the Government wants to create that poverty is actually reducing. For the bulk of Indians, today, the poverty level has, unfortunately, been rising. And, because of the global recession, now, that will become much worse in the days to come.

Look at the real health of our country. Every day, 1000 children die because of completely preventable disease, particularly, water-borne diseases. Thousand children a day! You have a situation where 56 per cent of our children do not get any vaccination or any protection; you have a situation where 40 per cent of our children are underweight; 70 per cent of our children are anaemic. I am quoting all this from the National Family Health Survey-III. They very clearly said that the

anaemia in our country is directly related to malnutrition. Nearly two-thirds of our pregnant mothers are anaemic. They are producing the future of India! And, this is the state of the future of India! This is the state of our mothers nad our children! And, if this is not a cause of concern, what else should be? Are we today happy tom-toming our economic achievements, while the bulk of India is actually suffering? It is actually suffering before the impact of global crisis has come. And, you have a situation, again, where 700 million people do not have access to ordinary toilets in our country.

Two-thirds of our coutnrymen don't have access to potable drinking water near their habitation. This is the real India. It is this India that we have to address our attention to, and not really be satisfied with all the glitter that you see in the Shinning India campaign. Fifty-four per cent of India consists of People who are below 25 years of age. The shoulders of that youth will build a new India. If those shoulders continue to be weakened by these sort of policies, then, what will be the future of this country? And, it is this important concern that doesn't reflect in hon. President's Address. On the contrary, what is the stark contrast we see? We see the glitzy scams of your Shinning India. You have had the Satyam scam. You have the scams connected with various SEZs. You have the Spectrum telecom scam. Regarding SEZs, this Government has said, and it is on record, that in four areas reforms will be brought about. On the question of land acquisition, I want to say that you are acquiring land on the basis of an antiquated 1894 Land Acquisition Act of British India. On the question of modern acquisition of land and how you have to give rehabilitation to land owners, four years have passed and nothing has come. On the question of facilities and tax concessions being given to SEZs, you said amendments will come, but, nothing has come. On the question of product mix within the SEZ; how much will be for production, how much will be for development or real estate development, changes had to be made, nothing has come. But, on the other hand, what is happening is, actually, facilitating, what the Prime Minister himself once called, 'crony capitalism'. On the one hand, you have crony capitalism being facilitated and, on the other hand, you have bulk of India suffering. It is this which is the actual Indian reality. On top of this comes the global economic recession. The President of India, in para 55, actually, anticipates what was said in the Interim Budget that was presented yesterday. It says, "We will be in a position to face this global recession". I said this yesterday and I repeat it today that not only the Address of the hon. President, but also the Interim Budget that was presented by the Government, both of them reflect a state a denial. This is a state of denial by the Government on the gravity of the impact of this global recession on us. According to even official estimates, in the organised labour force, more than five lakh employees have lost their jobs. It will run into crores in the unorganised sector, where they are dependent on various small, small jobs. Senesity is to this extent that 71 gem cutters and polishers in Surat in Gujarat have already committed suicide. The handloom weavers in Namakkal in Tamil Nadu are now

selling their kidneys in order to survive. This is the misery which this global recession is bringing about on our country. The impact of it is so deep and so agonising that we are refusing to recognise this reality, and, therefore, act accordingly. What is the way that we should act? The way we should have acted and we need to act is, immediately create a situation where you can generate massive levels of employment through big leaps in your public investment. We had hoped that that would come. We all understand the constitutional limitations of an interim budget. But the budget could have easily earmarked or suggested massive increases in investment and leave it to the next Government to decide how these expenditures would be handled. One way of handling could be monetising these expenditures, that is, by increasing the deficit. The other way would be to collect revenues through additional taxation. But that could be the decision of the next Government. We can't absolve our responsibility for the next four months, we meaning, the Indian Parliament, to our people. Many people adulate the United States of America. But, remember, George Bush left for Obama a budget deficit of more than one trillion doolars. Obama, instead of complaining, has gone forward and has now offered many more other schemes which, again, as their class character would have it, are more to bail out the corporates rather than empower the people. That is a different issue.

So, that course could have been adopted. Instead, what do we have Sir? In the Budget, the incremental increase in the Capital plan expenditure, incremental increase from the Budget figures is to the tune of about Rs. 40,000 crores. Much has been announced- about one lakh and some thousand crores on all the flagship programmes and about rs. 70 crores for infrastrucrure programmes. Much of these are allocations which have already been made. The additional allocations which have alrady been made. The additional allocation that has come is only about Rs. 40,000 crores, which is less than 1 per cent of our GDP. If this is inadequre, what is worse, today, with great pride-it was announced as one of the biggest achievements -- we heard Shri Aggarwal my learned colleague, talked amount the Rural Employment Guarantee Scheme. Yet, we had supported it. We wanted it. We implemented in a better way. We have a criticism on where the weakness are. It should be improved. But, during the Budget Speech, it was said that last year we spent Rs. 36,750 crores. What is the allocation for next year? It is Rs. 30,100 crores. That is, you have reduced it by Rs. 6,650 crores. You talked about rural development. What did we spend last year? It was Rs.56,883 crores/ What have you allocatred for next year? It is Rs. 30,000 crores. That is, you have reduced it by Rs. 6,650 crores. You talked about rural development. What did we spend last year? It was Rs. 56,883 croers. What have you allocated for next year? It is Rs. 51,706/- crores. That is Rs. 5,176 crores less. We talked about JNNURM and urban development. We spent about Rs. 6,420/- crores last year. Today, you are allocating Rs. 4,685/- crores. That is, you have

reduced it by Rs. 1,234/- crores. What are we doing, Sir? On the one hand, everybody talks of fiscal stimulus. We talk of greater public investment. That is the only way out; otherwise we cannot protect our people. On the other hand , in actual reality, you are reducing these allocations. That is why, I say, Sir, that the Government is in a state of denial . It is not realising the impact of this crisis that is there on our people. It is going to lead to ruination unless we act fast. And, that concern, however, is absent in the President's Address. Therefore, I think, it is not only in state of denail but it is still trapped in the neo-liberal framework of being concerned with fiscal fundamentsals. In times of recession, deficits are not of concern; it is neither economic sense nor common sense. In times of recession, no economy can come out of the recession without deficits. That is pure simple economics. The new in the US after the 1930's depression was all about deficits growing. Now, we are doing the exact opposite. What did we do? We moved specific amendments. But this reality must be taken into account. Please invest more, build the roads that are required, build the power generation capacities that are required, etc. Last year, we added 7,000 megawatts of power. For various other reasons, the hon. Leader of the Opposition referred to China. But the fact is, last year they added about 1,00,000 megawatts of power. I am not in a game of comparing ourselves with China, but it is a country with a population of similar size; it has similar problems. So much needs to be done. Invest more, build your power, give people more jobs, let them spend and on that basis let the economy grow. But the direction, Sir, somehow is missing and I think that needs to be corrected as this may have serious implications for our country and our people's future.

Another area which the hon. President has referred to and which is of a very serious concern is the whole area of social justice. The hon. President mentioned in para 21 that scholarships have been granted for minority children and some various lakhs etc. -- some figures were quoted -- but what is the fact, Sir? Not a single scholarship has been sanctioned tll date. And what is the reality again? You had the Sachar Committee Report. You had great fanfare, 15 point Prime Minister's Programme for minority welfare. What was the Budget allocation last year for minoity Welfare? It was Rs. 838 Crores.

Forget the fact that that was very low; but how much did they spend out of that? They spent only Rs. 523 crores. Rs. 315 crores allocated for minority welfare were not spent. What kind of concern is this? Similarly, if we look at what they had promised to the dalits, the CAG report for 2007-08 that came out recently shows special components and sub-plans for the SCs. What does it show -- Rs. 3,87,000 crores were denied to the SCs over the period of the last four years. Rs. 3,87,000 crores were sanctioned for them but it is not being spent for their welfare. And then, Government had

promised in the Common Minimum Programme that they would actively engage the private sector to ensure that reservations are extended to the private sector. Nothing has happened on that. Now, there is a bill. Unfortunately, I feel a little perturbed that none in this august House paid attention and in the din of the last day of the last session, this House passed a bill without anyone knowing what was happening in the House. By that, SCs are today denied the opportunity to enter any job in about 47 national instiutions of higher education. They cannot even enter the post of, what is called today in a favourable way, Assistant Professor, that is, Lecturer. They are debarred even at that level. I hope the other House will have the wisdom to not allow this Bill to be passed. What are we doing, Sir? On the one hand they are shedding tears for welfare, social justice, etc. while in reality this has been the track record of the Government.

Then, Sir, we heard a lot about terrorism. All of us are extremely concerned. I think there has been complete unanimity on this issue that as one India and one person, we should fight terrorism which is our enemy. We also, whether we practise it in reality or not, have at least formally accepted that terrorism knows no religion, region or caste; we will have to fight it together. We passed two Bills, which we felt, at that time, encroached upon the rights of the States and the federal structure, and at that point of time the hon. Home Minister had assured both the Houses that, in February, we will revisit these Bills. But nothing has happened and nothing has been brought before us. But the more important point. Sir, is that all these are concerned with after the event. What about pre-events profession? Our Intelligence gathering, Police modernisation, all that we talked of at the time Mumbai attacks! There is not even one word of that which is reflected in the hon. President's Address. So, if your fight against terrorism is to be taken forward, I think these essential concerns which are very important for us must find mention.

Finally, the last point that I want to make is this, since you are indicating about time. The hon. President mentioned the fact that we are entering the 60th year of Republic. The sixtieth year, for an ancient civilisation, is a very auspicious year. I mean all ancient civilisations in the world have and we call it *shashthi*. And after this year is over, we call it shashthi Poorthi, starting of another life, and another life means a new life. So, we are in that year, whether we follow policies which create a new life or whether we go back into the the morals of the past lives. And that is why, when we want to talk about the creation of a new life, we need to undestand what we are, because these acts of moral policing, these vigilante attacks, these acts of expression of a Hindutva-Taliban, this is something we cannot afford when we are going towards shashti poorthi. That is why, when the question comes up that we will protect our culture, what is our culture? In my opinion, there cannot be any other country where we have such a rich mosaic, a rich diversified mixture of various cultures, religions and traditions, as we have in India. Jawaharlal Nehru, on the eve of India's Independence, in the Dicsovery of India, evokes the example of a palimpsest - the palimpsest is an ancient tablet on which history is recorded and when the new victor comes, he erases the old history, and writes a

new history. But when he erases, he does not completely erase is because it cannot be completely erased. Talking about Indian culture, this is what Nehru said. He describes India as "An ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie have been inscribed and yet, no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously".

It is this richness that we have, Sir, and if anybody claims to be the sole custodian of this culture, it is something that cannot be permissible. You please go back to our Constitution, in the 60th year of the Republic. What doew Article 1 say? Article 1 says, "India, that is Bharat, shall be a Union of States." You remove 'that is Bharat'. The Constitution still retains the same contents but not th espirit. Why did we say 'that is Hind Bharat'? See the Constituent Assembly debates. There were a lot of debates whether it should be Hindustan, whether it should be Bharat, etc., etc. Finally the Constituent Assembly, after the partition, after the communal riots that took place, by its wisdom chose Bharat because of its secular connotation. I want to ruge you, what is the meaning Bharat? Some say, it is the name of son of Dushyant and Shakuntala who unfied this land; some say, it has a vedic interpretation, the vedic origin of Bharat Rishi. But there is another very important interpretation. Bharat is t econfluence of three themes -- Bha is for Bhavam, Ra is for Ragam and Tha is for Talam. It is only when you have a Raga that uses the seven musical notes in various combinations, you create a melody. When that melody is accompanied by a rhythem, talam you create a harmony and it is the expression of that harmony which is the character, that is the Bhava, and that is India. India is the confluence of all these rhythms and that is expressed in our character, which is Bharat. So, it is that character that we need to preserve. If that has to be strengthened, if that needs to be done, you require an alternative policy Tragestory an alternative to communalism, an alternative to the economic policies which need to be changed to be pro-people, an alternative which will keep the independence of our foreign policy and our dignity in the international community. The political alternative with these three policy alternatives, Sir, is the only basis for the future and better India. It is that alternative which we will have to strive for; it is that alternative that is missing in the President's Address. But we have an opportunity in our year of the Shasthi. We are going in for our fifteenth General Elections. Whether we will be able to create a new life for a new India will depend on whether we will install such an alternative, and that political alternative with that policy alternative is something that we require, and in that direction we will move some amendments to the hon. President's Address which we will take up at the later time. Thank you.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने धन्यवाद प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है। यह सही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना जो भाषण पढ़ा, वह बहुत ही लम्बा और नीरस भाषण था। अगर पूरे भाषण को पढ़ा जाए तो उसमें आम आदमी के बारे में बड़ी चर्चा की गई थी। उसमे यह कहा गया कि सबसे बड़ी और मूल बात यह है कि आम आदमी को क्या मिलेगा। आज असलियत यह है कि न तो आम आदमी को पीने का साफ पानी का साफ पानी मिल रहा है, न रोजगार की व्यवस्था है, न

मकान है, न शिक्षा है और न स्वास्थ्य है। जहां यह कहा जाता है कि हमने पिछले तीन-चार वर्षों में लगातार विकास दर को बहुत ऊंचा बनाए रखा और उसी विकास दर को ऊंचा बनाए रखने का ही यह परिणाम है कि उसका फायदा आम आदमी को मिल रहा है। परंतु मै ऐसा मानता हूं कि विकास दर जो बढ़ी, उसका जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इस संबंध में प्रोफेसर आमर्त्य सेन ने एक जगह लिखा है कि विकास दर ऊंची होने के बावजूद उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिला। मैं उन्हें कोट करता हूं : "Grwoth in India being maintained at high levels over the last few years, did not directly benefit the poor. Only a part of wealth actually flowed back to them and this too mainly because of increase in revenue collection." मान्यवर, उन्होंने यह बात कही क्योंकि आज अगर हम यथार्थ में या जमीनी स्तर पर हकीकत को देखें तो सही स्थिति का पता चलेगा। मान्यवर, अभी सीताराम येचुरी जी ने भी ठीक ही कहा कि जिस प्रकार से विषमता देश के अंदर बढ़ रही है, उसी का यह नतीजा है कि एक तरफ जो 'अकर्ता वर्ग' जो केवल तिकड़म से, केवल फ्रॉड करके, वर्तमान व्यवस्था को अपने हक में इस्तेमाल कर के पसीना बहाने वाले लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़प जाता है और दूसरी तरफ वह वर्ग है जो पुश्त-दर-पुस्त पसीना बहाता है, मेहनत करता है, परंतु उसके बावजूद उसको उसका हक नही मिलता। इस संबंध में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की बात सबसे ज्यादा कही गयी। मान्यवर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य बहुत अच्छा है, उसका उद्देश्य अच्छा है, परंतु हकीकत में उसमें सब को रोजगार नहीं मिलता और मान्यवर, यह विचित्र बात है कि जहां एक तरफ पढ़ने-लिखने वाले बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ रही हो, उनके रोजगार सृजन की बात न करके केवल गांव के गरीब लोगों के रोजगार की बात करना ठीक नहीं है और उसमें भी संपूर्ण रोजगार नहीं मिलता। प्रत्येक परिवार में केवल एक आदमी को ही मिलता है और वह भी सौ दिन का काम करता है। अगर आप इसका पूरा हिसाब लगाएं तो उसे औसतन् केवल 35-40 रुपया मिलता है। मान्यवर, एक तरफ देश में 5 लाख करोड़ की पूंजी है। अब चाहे वह रिलायंस के या दूसरे उद्योगपति हैं, 5 करोड़ की पूंजी और दूसरी तरफ रोजगार गारंटी योजना में एक साल के अंदर 5 हजार रुपए। तो आप इसे देखें कि 5 हजार रुपया एक के लिए और 5 लाख करोड़ रुपया एक के लिए।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि अभी जो वर्तमान बजट पेश किया गया है, उसमें पूरो मंत्रिमंडल पर 558 करोड़ रुपए का प्रावधान है और अगर प्रति मंत्री के हिसाब से यह पैसा बांट दिया जाए तो एक मंत्री के ऊपर 6 करोड़ रुपया आता है। एक तरफ मंत्री जी के ऊपर 6 करोड़ रुपए का खर्चा और दूसरी तरफ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक रोजगार पर साल में 5 हजार रुपया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें आप कैसे आम आदमी के भाग्य या आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कर सकते हैं?

मान्यवर, यहां पर तमाम प्रकार के कानूनों की बात कही गयी। ठीक है, अच्छे कानून बने, परंतु उनकानूनों का फायदा गरीबों को नहीं मिला। आज भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, उस पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की कोई बात इसमें नहीं कही गयी। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया। मान्यवर, वन मान्यता कानून है जिसके तहत वनवासी व आदिवासियों को अधिकार मिलने चाहिए। जंगल की जिन जमीनों पर उनका अधिकार था - उसके फल पर, उसकी लकड़ी पर, वहां की और चीजों पर से उनको बेदखल कर दिया गया है। आज भी वह एक्ट पास होने के बावजूद, उसे उसी कानून की शक्ल नही मिली है, उन्हें उसका अधिकार पत्र भी नहीं मिला है। अब खेती के बारे में चर्चा आई। खेती हमारी जीविका का सबसे प्रमुख साधन है और आप जानते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आज किसानों की आत्महत्या की रफ्तार में

किसी प्रकार की कोई कमी नही आ रही। एक यवतमाल जिला है जहां से प्रतिदिन 8 से 9 किसानों की आत्महत्या की खबर आती है। इसका क्या कारण है? खेती में जो सार्वजनिक निवेश होना चाहिए उसमें बिल्कुल कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। किसानो को न तो उचित पानी मिल रहा है और न ही बिजली मिल पा रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अगर वे मेहनत करके अपना अनाज पैदा करें तो समर्थन मूल्य तय करने में बेईमानी होती है। अगर समर्थन मूल्य तय भी हो जाए तो उसकी उचित खरीददारी नही होती। मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति जानता हूं और मध्य प्रदेश की स्थिति को भी जानता हूं कि जो धान बाजार में दो हजार रुपये का बिक रहा था, वह अब घटकर एक हजार रुपये हो गया। सरसों का दाम भी आधे से ज्यादा घट गया। उनकी ऊपज का दाम निरंतर घट रहा है। यह नुकसान भी किसान के ऊपर है। एक तो पैदावार की कमी, दूसरा, कृषि क्षेत्र के क्षेत्रफल की कमी और तीसरा, निवेश की कमी - यह सरकारी रिपोर्ट है जिसके अनुसार 60 सैकड़े से ज्यादा किसान इस स्थिति में है कि वे अपनी खेती के धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, परन्तु स्थिति इतनी विकट है कि उनके पास जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है। खाद पर जो सब्सिडी मिलती है, वह किसानों को सीधे नही मिलती। दिल्ली के केन्द्रीय मंत्री कहते है कि खाद की कोई कमी नहीं है। परन्तु आप राज्यों मे चले जाइए तो पता चलेगा कि खाद मिलती ही नही है। बीज की भी वही हालत है।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत साढ़े सात लाख जो दाइयां काम करती थी, उनको काम से बेदखल कर दिया गया। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे कानून बना दें, सारी व्यवस्था कर दें, परन्तु हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में इतना संकुचित है कि हमारे अंदर की जो संवेदनशीलता है, वह बिल्कुल खत्म हो जाती है।

आज हमारे सामने जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट है, रिसेसन है, उसके बारे में पहले तो हमारे यहां के योजनाकार और सरकार यह मानते थे कि उसका हम पर असर नही पड़ेगा, परन्तु आज हम देखते हैं कि उसका हमारे ऊपर व्यापक असर पड़ रहा है। हमारा जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व था, वह घट रहा है। हमारे जो बैंक हैं, उन बैंकों की लिक्विडिटी भी कम हो रही है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट मे कमी हो रही है। आज नये रोजगार का सृजन व्यापक पैमाने पर नहीं हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर लोगों की छंटनी हो रही है। आखिर यह जो भयावह स्थिति है, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? उसका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं अपने संसाधनों को सुरक्षित करें, उसे बचायें। अपने खर्चों पर और अपने लोभ पर संयम रखें। परन्तु आज स्थिति बहुत ही खराब है। मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है। एक तरफ केन्द्र सरकार की फिजूलखर्ची और दूसरी तरफ राज्य सरकारों की फिजूलखर्ची मैं और कुछ नही कहना चाहता, मगर मै उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइये, आपको पता चलेगा कि वहां के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका किस प्रकार से अपव्यय हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का जो बजट आया उसमें एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान मूर्तियों और पार्कों को बनाने के लिए कर दिया गया।

मैं अभी मिर्जापुर गया था। मैंने मिर्जापुर में देखा कि वहां लाल पत्थर के जो पहाड़ हैं, वे पहाड़ काटे जा रहे हैं, वहां पत्थर तराशे जा रहे है और वे सारे पत्थर लखनऊ मे लाकर पार्क और मूर्तियां बनाई जा रही हैं। वहां की नेता और मुख्य मंत्री को किसी ने बता दिया है कि अगर लाल पत्थर से मूर्ति बन जाए या लाल पत्थर से पार्क बन जाए तो वह 200, 300 साल तक रहेगा, जैसे दिल्ली या आगरा का लाल किला है। तो इस तरह से निमर्म होकर, निर्दयतापूर्वक अगर सरकारी संसाधनों का अपव्यय किया गया, अगर प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया गया, तो हम कहां खड़े रहेंगे? आज यही कारण है कि हमारी विश्वसनीयता घट रही है - राजनीति करने वालों, राजनीतिक संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रति जो आम जनता का विश्वास है, आज वह विश्वास घट रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : Mr. Tiwari, please listen.

श्री बृजभूषण तिवारी : सर, मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : No, no listen to me...*(Interruptions)*... थोड़ा सुनिए। Don't take the name of a person who cannot defend himself here.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : I am taking the name of a State. I am not taking the name of any individual.

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र और राज्य का संबंध है और हमेशा राज्य सरकारें यह शिकायत करती है कि केन्द्र से हमें भरपूर पैसा नहीं मिलता है, हमें पैकेज नहीं मिलता है, तो चाहे अपव्यय केन्द्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, आखिर यह अपव्यय तो जनता के पैसे का हो रहा है, हमारे देश के संसाधन का अपव्यय हो रहा है, इसलिए हमारी नज़र उस तरफ भी जानी चाहिए।

अगली बात मैं रक्षा के मामले में कहना चाहता हूं कि हमने इस बार बजट में रक्षा के लिए 34 फीसदी का प्रावधान बढ़ाया गया है। हम इसके खिलाफ नहीं है, आप रक्षा का प्रावधान बढ़ाइए, परन्तु जैसा कि कहा गया है कि जैसी रक्षा की तैयारी होनी चाहिए, वह तैयारी नहीं है-हथियार ठीक तरीके से नहीं है, वहां सैनिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे भी नहीं है। फिर. अभी जो घटना घटी, मुम्बई में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले से निबटने में जो हमारी अक्षमता रही, वह दूर होनी चाहिए। हम दूसरे पर, हम पाकिस्तान पर दोष तो मढ़ते रहे, परन्तु केवल पाकिस्तान पर दोष मढ़ने से हम अपनी जिम्मेदारियों से विरक्त नहीं हो जाते। इस बड़ी घटना ने देश की जनता को झकझोर दिया। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम लोग शुरु से ऐसा मानते रहे कि हम अपने पड़ोसी देशों से रिश्ता ठीक रखें। हम पाकिस्तान के साथ हुए बंटवारे को भी नकली बंटवारा मानते रहे, हम यह मानते रहे कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता मधुर हो, कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारा एक महासंघ बने, परन्तु उसी के साथ ही अगर पाकिस्तान में इस प्रकार की हरकतें होती हैं, जिनसे हमारी आजादी को खतरा हो, जिनसे हमारे देश को खतरा हो, जिनसे हमारी सम्प्रभुता को खतरा हो, तो उस खतरे का मुकाबला करने के लिए भी एक राष्ट्र के नाते हमको पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। अगर इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी हमले होते हैं तो एक राष्ट्र के नाते हमें इन आतंकवादी हमलों का मुकाबला इस तरह से करना चाहिए ताकि भविष्य में फिर कोई आतंकवादी हमला न हो, लेकिन मुम्बई में हुए आतंकी हमले के दौरान हमारी पूरी डिप्लोमसी केवल इसी बात पर लगी थी कि हम साक्ष्य इकट्ठे करें। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद अमेरिका हमारी मदद करे, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे देश हमारी मदद करें, परन्तु सभी ने कहा, सभी जानते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा होता है तो आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके लिए कोई संवेदना व्यक्त कर सकता है, आपके प्रति हमदर्दी व्यक्त कर सकता है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। परन्तु, हमारी तरफ से कोई ऐसा कठोर काम या कोई ऐसा कठोर निर्णय नहीं हुआ कि जिससे हम इन आतंकवादी हमलों का मुकाबला कर सकें, ताकि फिर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला न हो। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब कोई घटना घट जाती है, तो हम उसके बचाव में काम करते हैं और ये जो आतंकवादी संगठन हैं, आतंकवादी लोग हैं, ये हमेशा अपना लक्ष्य बदलते है, अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, अपना तौर-तरीका बदलते हैं और हम जब कोई घटना हो जाए, उसके बचाव में काम करते हैं। जैसे, यह पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जल मार्गों का भी इस्तेमाल आतंकवादी समूहों के द्वारा किय जा सकता है। अगर यह संभावना थी कि जलमार्गों

का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो हमें अपने जलमार्गों की सुरक्षा का भरपूर इंतजाम करना चाहिए था। अब जब घटना घट गई, जब मीटिंग्ज़ हो रही हैं, तब हमें सोचना पड़ रहा है, नीति बनानी पड़ रही है कि हम किस प्रकार से अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता है-पहली बात तो यह है कि आतंकवाद के प्रति हमारी क्या दृष्टि है, आतंकवाद के बारे में हमारी क्या strategy है, क्या रणनीति है। दूसरी बात यह है कि उस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी मशीनरी कैसी है। तीसरी बात यह है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वह कैसा है। चौथी बात यह है कि हमारी इच्छा शक्ति कैसी है, अगर हमारे अंदर willpower नहीं है, अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, अगर मुर्गी के कलेजे की तरह कहीं न्यूक्लियर वार न हो जाए, कोई दूसरा देश हमसे नाराज़ न हो जाए, अमरीका की इज़ाजत के बिना हम कभी बुरी परिस्थिति मे न फंस जाएं, अगर हमारा इस प्रकार का कमज़ोर मन, कमज़ोर दिल रहेगा, तो हम किसी भी इन आतंकवादी घटनाओं का मुकाबला नहीं कर सकते और यही स्थिति हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी है। हम यह मानते हैं कि चाहें पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या नेपाल का यह हिस्सा हो, इन देशों के साथ हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए, हमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां मदद करनी चाहिए क्योंकि यदि हमारे पास-पड़ोस के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, राजनीतिक दल मजबूत होते हैं, जनता और जनता के बीच सीधा संपर्क होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि पड़ोस के देशों में हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो हमारी जो सुरक्षा है, वह भी दृढ़ होगी, परन्तु इस सबके बावजूद मुझे प्रोफेसर अर्मत्य सेन की एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने यहां सांसदों को संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि हमारे यहां उपनिषदों मे या पुराने ग्रंथों मे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है-एक शब्द है 'नीति' और दूसरा शब्द है 'न्याय'... ये दोनों शब्द अलग हैं, 'नीति' अलग है 'न्याय' अलग है। 'नीति' का मतलब है व्यवस्था, 'नीति' का मतलब है विधान। तो हमारा विधान अच्छा है, हमारी व्यवस्था अच्छी है, हम अच्छे से अच्छे कानून पास करते हैं, हमारे पास मशीनरी है, पुलिस है, जुडिशियरी है, सदन है, राज्य सभा है, लोक सभा है, यह सारी व्यवस्था हमारे पास है, परन्तु इस व्यवस्था के बावजूद समाज का जो गरीब से गरीब आदमी है, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है, अगर उसके अंदर यह अहसास नहीं होता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमें इंसाफ मिल रहा है, तो इस नीति का भी कोई मतलब नहीं होता और जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज यही कारण है कि हमारे देश के अंदर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं।

अभी मुझे अखबारों में पढ़ने को मिला कि जो छत्तीसगढ़ और नागपुर का इलाका था, वहां पर 15 पुलिसकर्मी मारे गए और वे जो 15 पुलिसकर्मी मारे गए, उनका जो नेतृत्व कर रही थीं, वे औरतें थी, उन नक्सलपंथी औरतों का जो समूह था, उसकी नेता एक औरत थी और उन्होंने जिस तरीके से, जितने नृशंस और अमानवीय तरीके से उन पुलिसकर्मियों की हत्या की, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक औरत के बारे मे इस प्रकार की बात कभी सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन अगर दिमाग बिगड़ जाए, अगर वे गरीब और आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिनको अपना हक नहीं मिलता, जिनको अपना इंसाफ नहीं मिलता, अगर उनके मन में यह विद्रोह की बात आए, तो क्या आपकी यह नीति, आपकी व्यवस्था, आपकी संस्था उनको रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी।

आज आप देखिए कि सबसे बड़ा घोटाला सत्यम का है। अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि भ्रष्टाचार का 14.56 खरब डालर भारतीय लोगों का स्विटज़रलैंड के बैंकों में जमा है। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था कि यह जो विश्वव्यापी

आर्थिक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो टैक्स हैवन देश है-स्विटज़रलैंड, जहां दुनिया भर की काली कमाई का पैसा इकट्ठा होता है, वही पैसा इन दूसरे देशों में विशेषकर एशिया और अफ्रीका के देशों में खर्च हो रहा है, उसी पैसे के कारण उनका खर्चा, उनका रहन-सहन ऊंचाई की ओर बढ़ता है...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF P. J. KURIEN) : Now, it is 5.00 p.m. I think, it is the sense of the House to sit for another one hour....*(Interruptions)*... There are many speakers. So, we will extend up to one hour.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, अब कल किया जाए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) : कल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आज भी करना है।...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh) : Sir, today, make it half-an-hour. Tomorrow, we can get one hour...*(Interruptions)* ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : Mr. Minister, tell me whether half-an hour or one hour.

SHRI PAWAN BANSAL : Sir, I would request for one hour because there are many speakers. But, it is for the House to decide.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KUREIN) : Okay, Let us sit for one hour because there are a number of speakers. Now, the statement by the Minister.

STATEMENT BY MINISTER

Regarding Alleged Misbehaviour of Police in Jharkhand

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : This morning, hon. Member Shri Yashwant Sinha and certain other hon. Members made submissions on the incidents that took place at the gates of the Raj Bhawan in Ranchi, Jharkhand on February 12, 2009. I have been briefed on the submissions and I am distressed that such an incidents should have taken place on that day.

The Government of India has received information from the State Government. The DGP, Jharkhand has also report.

It is reported that prominent leaders of the BJP, along with a few thousands workers, marched towards the several gates of the Raj Bhawan. At gate no. 3, the demonstrators were led by two MLAs; they demonstrated peacefully behind the barricade; and there was no incident. At gate no. 4 the demonstrators were ley by an MLA; they also demonstrated peacefully behind the barricade and there was on incident.

The incident occurred between gate no. 2 and no.1 which is the main gate. It is reported that the demonstrators were led by Shri Yashwant Sinha, M.P., Shri Arjun Munda, MLA, Shri Saryu Rai, MLA, Shri Dinesh Sarangi, MLA, Shri Loknath Mahto, MLA and Shri Raghubar Das, MLA and States